

गरवी गुजरात

PRGI No. GJHIN/26/A1393

गरवी गुजरात

PUBLISHED HINDI DAILY FROM SURAT, AHMEDABAD, LUCKNOW

वर्ष : 01
अंक : 040
दि. 09.11.2026,
सोमवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा
SURAT EDITION

दस माह के अंतरराष्ट्रीय ऑपरेशन के बाद भारत लाया गया गैंगस्टर आफरीदी

30 से अधिक गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित गुरविंदर सिंह इथियोपिया से डिपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट पर पंजाब पुलिस ने लिया हिरासत में; पांच चर्चित हत्याकांडों में भी है आरोपी

चंडीगढ़। पंजाब में संगठित अपराध और गैंगस्टर नेटवर्क के खिलाफ चल रही कार्रवाई के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 30 से अधिक गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित गैंगस्टर गुरविंदर सिंह उर्फ आफरीदी को अफ्रीकी देश इथियोपिया से भारत लाया गया है। पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) ने केंद्रीय एजेंसियों और पंजाब पुलिस की ओवरसीज फ्यूजिटिव ट्रैकिंग एंड एक्सट्राडिशन सेल (ओएफटीईसी) के साथ समन्वय कर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। भारत पहुंचने पर दिल्ली एयरपोर्ट से पंजाब पुलिस ने उसे अपनी हिरासत में ले लिया। अब उसे पंजाब ले जाकर विभिन्न आपराधिक मामलों, उसके नेटवर्क और विदेश में छिपकर संचालित की जा रही गतिविधियों के संबंध में पूछताछ की जाएगी।

पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने इस कार्रवाई की जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देश पर चलाए जा रहे 'गैंगस्टरां ते वार' अभियान के तहत यह महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई है। पुलिस के मुताबिक, पंजाब पुलिस के इतिहास में यह पहला मौका है, जब किसी अफ्रीकी देश से राज्य के एक वांछित अपराधी को डिपोर्ट करवाकर भारत लाया गया है। इसे विदेश में छिपकर भारत में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने वाले गैंगस्टरों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर की गई बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है।

गुरविंदर सिंह उर्फ आफरीदी को भारत लाने के लिए पंजाब पुलिस ने करीब दस महीने तक विशेष अभियान चलाया था, जिसे 'ऑपरेशन शहीद' नाम दिया गया। इस अभियान के दौरान पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने उसकी गतिविधियों पर नजर रखने, संभावित ठिकानों का पता लगाने, खुफिया सूचनाएं जुटाने और विभिन्न देशों की सुरक्षा एजेंसियों के साथ संपर्क स्थापित करने पर लगातार काम किया। आरोपी लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था, ताकि भारतीय जांच एजेंसियों की पकड़ से बाहर रह सके। इसके बावजूद पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसके ठिकानों का पता लगाने का प्रयास जारी रखा। इस पूरे अभियान की निगरानी



एजीटीएफ के विशेष पुलिस महानिदेशक प्रमोद बान कर रहे थे। वहीं, काउंटर इंटेलिजेंस विंग के अंतर्गत ओएफटीईसी के आईजी आशीष चौधरी ने अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय और आगे की कार्रवाई की जिम्मेदारी संभाली। पंजाब पुलिस के अनुसार, लगातार जुटाई गई खुफिया जानकारी और विभिन्न देशों की एजेंसियों के सहयोग से आखिरकार आरोपी तक पहुंचने में सफलता मिली। पुलिस की जांच में सामने आया कि गुरविंदर सिंह उर्फ आफरीदी 31 मार्च 2025 को मुंबई एयरपोर्ट से संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) फरार हुआ था। विदेश जाने के लिए उसने कथित तौर पर गोरखपुर के रहने वाले एक व्यक्ति की फर्जी पहचान के आधार पर तैयार कराया गया पासपोर्ट इस्तेमाल किया था। बताया गया है कि यह पासपोर्ट 12 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जारी किया गया था। फर्जी पहचान के सहारे देश से बाहर निकलने के बाद उसने लगातार अपने ठिकाने बदले और अलग-अलग देशों में जाकर गिरफ्तारी से बचने की कोशिश की।

पंजाब पुलिस के मुताबिक, विदेश पहुंचने के बाद शुरुआत में आफरीदी यूएई में छिपा रहा। वहां से उसने इस्तांबुल के रास्ते मैक्सिको जाने की कोशिश की, लेकिन उसकी यह योजना सफल नहीं हो सकी। उसे मैक्सिको पहुंचने से पहले ही वापस यूएई भेज दिया गया। इसके बाद उसने फिर अपना ठिकाना बदल लिया और अलग-अलग देशों में जाकर छिपने लगा। पुलिस के अनुसार, अप्रैल 2026 में वह यूएई से केन्या पहुंचा। जून 2026 में केन्या से अंगोला चला गया और नवंबर 2026 में अंगोला से इथियोपिया पहुंचा। इस तरह वह लगातार देश बदलकर भारतीय एजेंसियों की कार्रवाई से बचने का प्रयास करता रहा।

आरोपी की तलाश में पंजाब पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कानूनी और खुफिया कार्रवाई की थी। उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया गया था। इसके अलावा इंटरपोल के माध्यम से सात अलग-अलग रेफरेंस जारी हुए थे। पुलिस ने आरोपी के फर्जी पासपोर्ट, विदेश में उसकी गतिविधियों और संभावित ठिकानों से जुड़ी सूचनाएं समय-समय पर केंद्रीय एजेंसियों तथा संबंधित अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ साझा कीं। लगातार निगरानी और सूचनाओं के आदान-प्रदान के बाद छह नवंबर 2026 को इथियोपिया में उसे हिरासत में ले लिया गया। आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसे भारत डिपोर्ट किया गया।

पंजाब पुलिस के अनुसार, गुरविंदर सिंह उर्फ आफरीदी के खिलाफ देश में 30 से अधिक गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें हत्या, हत्या के प्रयास, जबरन वसूली और आर्म्स एक्ट से जुड़े मामले शामिल हैं। पुलिस का दावा है कि वह पंजाब में हुए कई चर्चित हत्याकांडों में वांछित है। उसके खिलाफ पांच हत्या के मामलों में विशेष रूप से तलाश की जा रही थी। इन मामलों में आम आदमी पार्टी से जुड़े सरपंच, एक नाबालिग बच्चे, स्थानीय स्तर पर सक्रिय व्यक्तियों और कांग्रेस के एक पदाधिकारी की हत्या के मामले शामिल हैं।

पुलिस के मुताबिक, अक्टूबर 2024 में आम आदमी पार्टी के सरपंच राजविंदर सिंह उर्फ राज तलवंडी की हत्या हुई थी। इस मामले में आफरीदी वांछित बताया गया है। इसके बाद मार्च 2025 में 12 वर्षीय गुरसेवक सिंह की हत्या के मामले में भी उसका नाम सामने आया। इसी महीने विक्की चुघ की हत्या के मामले में भी पुलिस को उसकी तलाश थी। मई 2025 में जसवंत सिंह की हत्या के मामले में भी उसे आरोपी बताया गया है। वहीं, सितंबर 2025 में कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष गुरमेल सिंह की हत्या के मामले में भी पंजाब पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। इन सभी मामलों में उसकी कथित भूमिका की जांच और संबंधित साक्ष्यों का परीक्षण अब आगे की पूछताछ का अहम हिस्सा होगा। पुलिस का मानना है कि आफरीदी की गिरफ्तारी से पंजाब में सक्रिय आपराधिक गिरोहों के नेटवर्क और विदेश में छिपे उनके सहयोगियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां मिल सकती हैं। जांच एजेंसियां यह पता लगाने का प्रयास करेंगी कि वह विदेश में रहते हुए किन लोगों के संपर्क में था, भारत में उसके गिरोह का संचालन कौन कर रहा था और आपराधिक गतिविधियों के लिए हथियारों तथा धन की व्यवस्था किस तरह की जाती थी। इसके साथ ही जबरन वसूली, हत्या की साजिश और अन्य वारदातों में कथित तौर पर शामिल सहयोगियों की भूमिका की भी पड़ताल की जाएगी। विदेश में छिपे गैंगस्टरों को वापस लाने के लिए भारतीय एजेंसियों के सामने कई तरह की चुनौतियां होती हैं। ऐसे अपराधी फर्जी दस्तावेजों, बदली हुई पहचान और लगातार बदलते ठिकानों के सहारे गिरफ्तारी से बचने की कोशिश करते हैं। अलग-अलग देशों के कानून, प्रत्यर्पण या निर्वासन की प्रक्रिया और संबंधित एजेंसियों के बीच समन्वय भी कार्रवाई को जटिल बनाते हैं। ऐसे में करीब दस महीने तक चले 'ऑपरेशन शहीद' की सफलता पंजाब पुलिस के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। गुरविंदर सिंह उर्फ आफरीदी को भारत लाए जाने के बाद अब जांच का अगला चरण शुरू होगा। पुलिस उससे अलग-अलग मामलों में पूछताछ कर सकती है और उसके कथित आपराधिक नेटवर्क से जुड़े लोगों की पहचान करने का प्रयास करेगी। हालांकि, जिन हत्याकांडों और अन्य अपराधों में उसे आरोपी बताया गया है, उनमें उसकी भूमिका का अंतिम निर्धारण जांच और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर ही होगा।

ईडी कोई 'सुपर कॉप' नहीं, कानून के दायरे में रहकर करे जांच : कर्नाटक हाई कोर्ट

बेंगलुरु। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच और उसके अधिकारों को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। अदालत ने स्पष्ट किया कि ईडी कोई 'सुपर कॉप' नहीं है, जो अपनी जानकारी में आने वाले हर मामले की जांच अपने स्तर पर शुरू कर दे। धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एजेंसी की जांच की अपनी कानूनी सीमाएं हैं और उसे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही कार्रवाई करनी होगी। अदालत ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए उससे जुड़ा मूल अपराध यानी अनुसूचित अपराध (प्रेडिकेट ऑफेंस) मौजूद होना जरूरी है। यदि मूल अपराध ही कानूनी रूप से समाप्त हो जाता है, तो उससे जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की कार्यवाही भी आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। न्यायमूर्ति एम.आई. अरुण की पीठ ने कांग्रेस नेता के.वाई. नंजे गौड़ा और अन्य के खिलाफ चल रही मनी लॉन्ड्रिंग की कार्यवाही रद्द करते हुए यह टिप्पणी की। अदालत ने यह भी साफ किया कि यदि ईडी की जांच के दौरान किसी अन्य अनुसूचित अपराध से संबंधित जानकारी सामने आती है, तो एजेंसी उसे संबंधित पुलिस या जांच संस्था के साथ साझा कर सकती है, लेकिन संबंधित एजेंसी की ओर से कार्रवाई नहीं होने पर ईडी स्वयं मजिस्ट्रेट अदालत में निजी शिकायत दर्ज कर उस अपराध की जांच शुरू कराने का अधिकार नहीं रखती। पीएमएलए में एजेंसी को ऐसी स्वतंत्र शक्ति नहीं दी गई है। हाई कोर्ट ने मामले में याचिकाकर्ता से जब्त की गई वस्तुएं भी लौटाने का निर्देश दिया।



अदालत ने अपने फैसले में कहा कि पीएमएलए के तहत ईडी की शक्तियां स्वतंत्र और असीमित नहीं हैं। यह कानून दूसरे कानूनों के तहत दर्ज कुछ निर्धारित अपराधों से जुड़ी अवैध कमाई और धनशोधन की जांच का अधिकार देता है। इसलिए केवल किसी गतिविधि पर संदेह होने या जांच के दौरान अनियमितता सामने आने से ईडी अपने स्तर पर नया आपराधिक मामला शुरू नहीं कर सकती। इसके लिए जरूरी है कि संबंधित अपराध कानून की अनुसूची में शामिल हो और उसके संबंध में निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत मामला मौजूद हो। हाई कोर्ट ने पीएमएलए की धारा 66(2) का उल्लेख करते हुए कहा कि यदि ईडी को अपनी जांच के दौरान किसी दूसरे अनुसूचित अपराध से जुड़ी जानकारी मिलती है, तो उसे संबंधित पुलिस या जांच एजेंसी को इसकी सूचना देनी चाहिए। इसके बाद उस अपराध के संबंध में कार्रवाई करना संबंधित एजेंसी के अधिकार क्षेत्र में आता है। ईडी सूचना साझा करने की भूमिका निभा सकती है, लेकिन उसे यह अधिकार नहीं है कि संबंधित पुलिस की निष्क्रियता के आधार पर वह खुद निजी शिकायत दर्ज कर जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ाए। अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और विभिन्न जांच एजेंसियों को अपने निर्धारित अधिकार क्षेत्र में रहकर काम करना चाहिए। यह पूरा मामला कर्नाटक के कोलार जिले के मालूर में भूमि आवंटन से जुड़ा है। कांग्रेस नेता के.वाई. नंजे गौड़ा उस समय भूमि आवंटन समिति के अध्यक्ष थे। आरोप लगाया गया था कि उन्होंने समिति के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर करीब 38 लोगों को 80 एकड़ जमीन आवंटित करने की सिफारिश की थी। शिकायत में कहा गया कि इस प्रक्रिया में पद का दुरुपयोग किया गया और जमीन आवंटन में कथित तौर पर नियमों का उल्लंघन हुआ। सामाजिक कार्यकर्ता के.सी. राजन्ना ने वर्ष 2022 में बेंगलुरु की अदालत में नंजे गौड़ा और अन्य लोगों के खिलाफ निजी शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत के आधार पर धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश सहित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ। ईडी ने भूमि आवंटन से जुड़े इस मामले को मूल अपराध मानते हुए वर्ष 2023 में पीएमएलए के तहत जांच शुरू की थी। एजेंसी का उद्देश्य कथित अवैध गतिविधियों से जुड़े वित्तीय लेनदेन और धनशोधन के पहलुओं की पड़ताल करना था। जांच आगे बढ़ने पर ईडी को कोलार और चिक्काबल्लापुर मिल्क यूनियन लिमिटेड में कर्मचारियों की भर्ती से जुड़ी कथित अनियमितताओं की जानकारी मिली। एजेंसी को संदेह था कि भर्ती प्रक्रिया में भी गड़बड़ी हुई है।

व्हाट्सएप पर सोनिया-राहुल के खिलाफ टिप्पणी करना पड़ा भारी, 85 वर्षीय बुजुर्ग पर मुकदमा

तिरुवनंतपुरम। सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर किसी के खिलाफ अपमानजनक या मानहानिकारक टिप्पणी करना कानूनी मुश्किलों का कारण बन सकता है। ऐसा ही एक मामला केरलम की राजधानी तिरुवनंतपुरम में सामने आया है, जहां कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ व्हाट्सएप ग्रुप में कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणियां पोस्ट करने के आरोप में 85 वर्षीय बुजुर्ग के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी पर दोनों नेताओं की छवि खराब करने और उनकी सार्वजनिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से संदेश साझा करने का आरोप है। पुलिस ने आरोपी की पहचान तिरुवनंतपुरम के थाइकाउड निवासी रवींद्रनाथन नायर के रूप में की है। इस मामले में तिरुवनंतपुरम सिटी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में चार नवंबर को एक कांग्रेस नेता की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि नायर ने 'त्रिवेंद्रम क्लब सीनियर्स फोरम TVM क्लब' नाम के व्हाट्सएप ग्रुप में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक संदेश पोस्ट किए थे। आरोप है कि आरोपी ने जानबूझकर ऐसे संदेश साझा किए, जिनमें दोनों नेताओं के प्रति अपमानजनक टिप्पणियां की गई थीं। चूंकि यह एक सामूहिक व्हाट्सएप ग्रुप था, इसलिए वहां मौजूद अन्य सदस्य भी इन संदेशों को देख सकते थे। शिकायतकर्ता का कहना है कि टिप्पणियों का उद्देश्य दोनों नेताओं को बदनाम करना और समाज में उनकी सार्वजनिक छवि तथा प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना था। इसी आधार पर पुलिस से कानूनी कार्रवाई की मांग की गई थी। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच शुरू की और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (आईटी एक्ट) की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया। फिलहाल पुलिस शिकायत में लगाए गए आरोपों और संबंधित डिजिटल सामग्री के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है। हालांकि, अभी तक मामले में आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों की न्यायिक पुष्टि नहीं हुई है। यह मामला ऐसे समय सामने आया है, जब सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप पर साझा की जाने वाली सामग्री को लेकर कानूनी जिम्मेदारी का सवाल लगातार महत्वपूर्ण होता जा रहा है। अक्सर लोग व्हाट्सएप ग्रुप को निजी बातचीत का माध्यम समझकर ऐसी टिप्पणियां कर देते हैं, जिन्हें बाद में दूसरे सदस्य शिकायत या कानूनी कार्रवाई का आधार बना सकते हैं। किसी व्यक्ति या सार्वजनिक हस्ती के खिलाफ की गई टिप्पणी यदि मानहानिकारक या कानून का उल्लंघन करने वाली पाई जाती है, तो शिकायत के आधार पर पुलिस जांच कर सकती है। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मौजूद है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी के खिलाफ निराधार आरोप, अपमानजनक सामग्री या प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाले संदेश साझा करने की खुली छूट मिल जाती है। किसी टिप्पणी की प्रकृति, उसके संदर्भ, उपलब्ध साक्ष्य और संबंधित कानूनी प्रावधानों के आधार पर पुलिस कार्रवाई का निर्णय लिया जाता है। तिरुवनंतपुरम का यह मामला भी इसी कानूनी पहलू को सामने लाता है। फिलहाल 85 वर्षीय रवींद्रनाथन नायर के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी है। जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि व्हाट्सएप ग्रुप में साझा किए गए संदेशों की वास्तविक प्रकृति क्या थी और शिकायत में लगाए गए आरोपों के समर्थन में कितने साक्ष्य उपलब्ध हैं।



दिवाली की खुशियां मातम में बदलीं, भीषण आग में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत

जाजपुर। दीपावली की तैयारियों के बीच ओडिशा के जाजपुर जिले में हुए भीषण अग्निकांड ने एक परिवार की खुशियां छीन लीं। शनिवार रात एक घर में अचानक आग लगने से दो मासूम बच्चों समेत एक ही परिवार के चार सदस्यों की दर्दनाक मौत हो गई। आग इतनी तेजी से फैली कि घर के भीतर मौजूद लोगों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। हादसे में परिवार का एक अन्य सदस्य भी गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए कटक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है और मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

यह हृदयविदारक घटना जाजपुर जिले के बालिचंद्रपुर थाना क्षेत्र के नालीपुर गांव की है। पुलिस के अनुसार, शनिवार रात करीब 8:30 बजे निजामुद्दीन के घर में आग लगी। उस समय परिवार के सदस्य रात के भोजन की तैयारी कर रहे थे। घर में मौजूद तबस्सुम (42) और उनकी बेटी गुलअफ्सा (27) एलपीजी गैस का इस्तेमाल कर खाना बना रही थीं। गुलअफ्सा अपने बच्चों के साथ मायके आई हुई थीं। इसी दौरान घर में अचानक आग भड़क उठी और देखते ही देखते उसने पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया।

हादसे में तबस्सुम, उनकी बेटी गुलअफ्सा और गुलअफ्सा के दो बच्चों की मौत हो गई। मृतक बच्चों की उम्र क्रमशः 10 और आठ वर्ष बताई गई है। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि घर के भीतर मौजूद लोगों को सुरक्षित बाहर निकलने का अवसर नहीं मिल सका। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आग ने कुछ ही समय में पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया और मकान का बड़ा हिस्सा जलकर राख हो गया। दीपावली से ठीक पहले एक ही परिवार के चार लोगों की मौत की खबर से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस के मुताबिक, इस हादसे में परिवार का एक 22 वर्षीय युवक भी गंभीर रूप से झुलस गया। आग की चपेट में आने के बाद उसे तत्काल बचाकर बड़चना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। वहां चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए बेहतर उपचार के लिए कटक स्थित एससीबी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल रेफर कर दिया। युवक की स्थिति को लेकर परिवार के लोग चिंतित हैं। घटना की सूचना मिलते ही चांदीखोल अग्निशमन केंद्र की टीम और बालिचंद्रपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। दमकलकर्मियों ने आग बुझाने और घर में फंसे लोगों को बचाने के लिए अभियान शुरू किया। हालांकि, आग की भयावहता और मकान की बनावट के कारण राहत एवं बचाव कार्य में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। चांदीखोल अग्निशमन केंद्र के अधिकारी संतोष कुमार स्वाईं ने घटना की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि घर से बाहर निकलने के लिए केवल एक ही दरवाजा था। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, घर के सदस्य इसी वजह से समय रहते बाहर नहीं निकल पाए और आग में फंस गए। आग लगने के कारणों का फिलहाल स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। प्रारंभिक जानकारी में एलपीजी गैस के इस्तेमाल के दौरान आग फैलने की बात सामने आई है, लेकिन पुलिस और अग्निशमन विभाग इसकी वास्तविक वजह का पता लगाने में जुटे हैं। यह जांच की जा रही है कि आग गैस रिसाव, सिलेंडर या खाना पकाने के दौरान किसी अन्य कारण से लगी थी।

राजस्थान ने खोया अनुभवी राजनीतिक चेहरा भाजपा विधायक जसवंत यादव का निधन

जयपुर। राजस्थान की राजनीति के लिए रविवार का दिन दुखद खबर लेकर आया। बहरोड़ विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक और प्रदेश सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. जसवंत यादव का 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने जयपुर में कैंसर से लंबी लड़ाई लड़ने के बाद रविवार सुबह 8:15 बजे अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर सामने आते ही राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में शोक की लहर दौड़ गई। भाजपा नेताओं, जनप्रतिनिधियों, समर्थकों और क्षेत्र के लोगों ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी उनके निधन पर शोक जताते हुए इसे प्रदेश की राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति बताया। डॉ. जसवंत यादव के निधन की जानकारी उनके बेटे मोहित यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से साझा की। उन्होंने भावुक संदेश में बताया कि उनके पूजनीय पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। मोहित यादव ने अपने संदेश में पिता के व्यक्तित्व को याद करते हुए कहा कि उनका स्नेह, सादगी और समाज के प्रति समर्पण हमेशा लोगों की स्मृतियों में जीवित रहेगा। परिवार के लिए यह कठिन समय है, वहीं उनके समर्थकों और राजनीतिक सहयोगियों के बीच भी शोक का माहौल है। लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे जसवंत यादव के निधन से उनके समर्थकों को गहरा आघात पहुंचा है। राजस्थान की राजनीति में डॉ. जसवंत यादव की पहचान एक अनुभवी और सक्रिय जनप्रतिनिधि के रूप में रही। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत वर्ष 1998 में मुंडावर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर की थी। पहली ही जीत के साथ उन्होंने क्षेत्रीय राजनीति में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। इसके अगले ही वर्ष



1999 में वे अलवर लोकसभा क्षेत्र से सांसद निर्वाचित हुए। विधानसभा से संसद तक का उनका राजनीतिक सफर उनकी लोकप्रियता और क्षेत्र में राजनीतिक पकड़ को दर्शाता है। उन्होंने जनता से जुड़े मुद्दों को राजनीतिक मंचों पर उठाया और प्रदेश की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई। डॉ. जसवंत यादव चार बार विधायक चुने गए। इसके अलावा उन्होंने लोकसभा में अलवर का प्रतिनिधित्व भी किया। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली सरकार में उन्होंने वर्ष 2016 से 2018 तक कैबिनेट मंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभाई। मंत्री रहते हुए उन्होंने सरकार के कामकाज और विभिन्न प्रशासनिक एवं राजनीतिक गतिविधियों में भूमिका निभाई। उनके लंबे राजनीतिक अनुभव के कारण भाजपा संगठन और प्रदेश की राजनीति में उन्हें महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। बहरोड़ क्षेत्र में उनकी पहचान एक ऐसे नेता के रूप में रही, जिन्होंने लंबे समय तक चुनावी राजनीति में सक्रिय रहकर जनता के बीच अपना आधार बनाए रखा। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने उन्हें बहरोड़ सीट से उम्मीदवार बनाया था। इस चुनाव में जीत दर्ज कर वे एक बार फिर विधानसभा पहुंचे। विधायक के रूप में वे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उनके निधन से बहरोड़ विधानसभा क्षेत्र ने अपना निर्वाचित प्रतिनिधि खो दिया है। उनके जाने से राजस्थान विधानसभा में सदस्यों की संख्या घटकर 199 रह गई है। अब बहरोड़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव की स्थिति बन गई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इस सीट पर छह महीने के भीतर उपचुनाव होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि चुनाव की औपचारिक प्रक्रिया और तारीखों का निर्धारण निर्वाचन आयोग की ओर से किया जाएगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डॉ. जसवंत यादव के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपने शोक संदेश में लिखा कि बहरोड़ के विधायक डॉ. जसवंत यादव के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। इस कठिन घड़ी में उनकी गहरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों और समर्थकों के साथ हैं। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान देने तथा परिवार और समर्थकों को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री के संदेश के बाद भाजपा के अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। परिवार की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, रविवार शाम चार बजे के बाद डॉ. जसवंत यादव का पार्थिव शरीर अलवर के जसवंत नगर स्थित उनके आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। यहां परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, राजनीतिक सहयोगी और क्षेत्र के लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे सकेंगे। उनके अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में समर्थकों और परिचितों के पहुंचने की संभावना है। इसके बाद सोमवार, 9 नवंबर को दोपहर तीन बजे उनके पैतृक गांव सिलपाटा में अंतिम संस्कार किया जाएगा। यह गांव खैरथल-तिजारा जिले में स्थित है। परिवार के सदस्य और समर्थक अंतिम संस्कार में शामिल होकर उन्हें अंतिम विदाई देंगे।

डॉ. जसवंत यादव का राजनीतिक जीवन करीब तीन दशकों तक फैला रहा। वर्ष 1998 में विधानसभा चुनाव से शुरू हुआ उनका सफर लोकसभा तक पहुंचा और फिर राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी तक विस्तारित हुआ। अलग-अलग राजनीतिक भूमिकाओं में उन्होंने अलवर और आसपास के क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया। उनके निधन से भाजपा ने एक अनुभवी जनप्रतिनिधि खो दिया है। वहीं बहरोड़ क्षेत्र के लोगों के लिए भी यह व्यक्तिगत और राजनीतिक दोनों स्तरों पर बड़ी क्षति है। चुनावी राजनीति में लंबे समय तक सक्रिय रहने वाले नेताओं की पहचान केवल उनके पदों से नहीं बनती, बल्कि जनता के साथ उनके संपर्क, क्षेत्र में उनकी मौजूदगी और राजनीतिक अनुभव से भी बनती है। जसवंत यादव ने अपने सार्वजनिक जीवन में इन सभी पहलुओं के माध्यम से अपनी पहचान स्थापित की थी।

उनके निधन के बाद अब उनके समर्थकों और क्षेत्र के लोगों के बीच उनकी राजनीतिक यात्रा और सार्वजनिक जीवन की यादें चर्चा में हैं। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लंबी लड़ाई के बाद उनका जाना परिवार के लिए गहरा दुख लेकर आया है। प्रदेश की राजनीति में उनके अनुभव और सक्रियता की कमी महसूस की जाएगी। सोमवार को पैतृक गांव में होने वाला अंतिम संस्कार उनके सार्वजनिक जीवन को अंतिम विदाई देने का अवसर होगा, जहां राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।

शतायु की दहलीज पर आडवाणी, जन्मदिन पर घर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी

नई दिल्ली। भारतीय राजनीति के वरिष्ठतम नेताओं में शामिल पूर्व उप प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने रविवार को अपना 99वां जन्मदिन मनाया। इस खास अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके आवास पहुंचे और उन्हें जन्मदिन की बधाई देते हुए स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना की। आडवाणी के जीवन के 100वें वर्ष में प्रवेश करने पर प्रधानमंत्री ने उनके राजनीतिक योगदान, वैचारिक दृढ़ता और संगठन निर्माण में निभाई गई भूमिका को याद किया। इस दौरान उनके आवास पर शुभचिंतकों, पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी भी रही।

लालकृष्ण आडवाणी का जन्म 8 नवंबर 1927 को हुआ था। रविवार को 99 वर्ष पूरे करने के साथ ही उन्होंने जीवन के 100वें वर्ष में प्रवेश किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर को विशेष बताते हुए उन्हें शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि आठ नवंबर का दिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन आडवाणी अपने जीवन के 100वें वर्ष में कदम रख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए इस विशेष अवसर पर अपनी हार्दिक शुभेच्छाएं प्रकट कीं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आडवाणी के जीवन और राजनीतिक सफर पर एक विशेष लेख भी लिखा। इसमें उन्होंने भारत के प्रति उनके अमूल्य योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि उनका जीवन संघर्ष, समर्पण, संगठन निर्माण और राष्ट्रसेवा की प्रेरक यात्रा रहा है। प्रधानमंत्री ने उनके जीवन के विभिन्न पड़ावों को याद करते हुए विभाजन की त्रासदी से लेकर भारतीय राजनीति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका तक का जिक्र किया।

पीएम मोदी ने लिखा कि आडवाणी ने विभाजन की भयावहता का सामना किया और शून्य से अपने जीवन का पुनर्निर्माण किया। इसके बाद उन्होंने जनसंघ को



मजबूत करने और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए उनका संघर्ष, सोमनाथ से अयोध्या तक निकाली गई रथयात्रा का नेतृत्व और सरकार में रहते हुए राष्ट्र की सेवा उनके सार्वजनिक जीवन के उल्लेखनीय अध्याय रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी के बीच दशकों तक चली राजनीतिक साझेदारी को भी भारतीय राजनीति में आपसी विश्वास, सम्मान और सहयोग का विशिष्ट उदाहरण बताया। उनके अनुसार, दोनों नेताओं की जोड़ी ने भारतीय राजनीति को नई दिशा देने में महत्वपूर्

चाय पर चर्चा

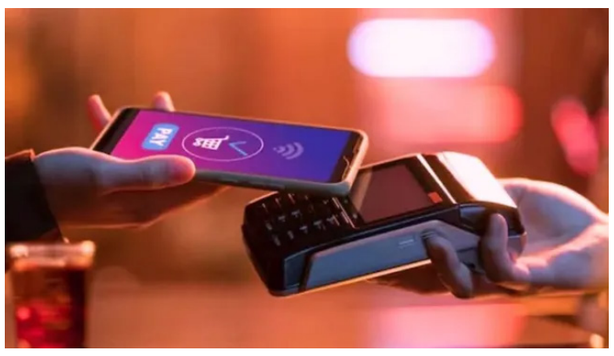
प्रकाश की आकांक्षा का अनूठा उत्सव

संध्या उतरती है। घरों की देहरियों पर दीप जलने लगते हैं। कहीं मिट्टी के छोटे दीयों में तेल की लौ कांपती है, कहीं रंगीन रोशनियां दीवारों पर अपना उत्सवी विस्तार रचती हैं। आकाश में आतिशबाजी के फूल खिलते हैं और कुछ क्षणों के लिए रात अपनी पहचान भूल जाती है। दीपावली का यह दृश्य हर वर्ष लौटता है, फिर भी उसकी प्रतीक्षा पुरानी नहीं पड़ती। शायद मनुष्य के भीतर प्रकाश की एक ऐसी आकांक्षा है, जिसे समय की कोई ऋतु समाप्त नहीं कर सकती। वह बाहर दीप जलाता है, लेकिन भीतर एक प्रश्न जागता रहता है- क्या जीवन में सचमुच कुछ उजाला हुआ? प्रकाश केवल अंधेरे का प्रतिपक्ष नहीं है। वह देखने की नई संभावना है। अंधेरे में वस्तुएं अपनी सीमाएं खो देती हैं, प्रकाश उन्हें पहचान लौटाता है। दीपावली का आत्मीय अर्थ तब खुलता है, जब मनुष्य बाहरी जगमगाहट से हटकर अपने भीतर देखता है। उत्सव की असली शुरुआत घर के बाहर नहीं, दृष्टि के भीतर होती है। दीपावली की तैयारी घर की साफ-सफाई से आरंभ होती है, लेकिन धूल केवल वस्तुओं पर नहीं जमती। समय की परतें मन पर भी उतरती हैं। प्रकाश पर्व पर घर सजाना अपने संसार को फिर से रचने जैसा है। कोई दरवाजे पर तोरण बांधता है, कोई चौखट पर रंगोली बनाता है, कोई मिट्टी के दीपों को अपने हाथों से रंगता है। फूलों की पंखुड़ियां आंगन में बिखरती हैं, तो लगता है जैसे प्रकृति ने घर के लिए छोटा सा पत्र भेजा हो।

रंगोली मिट जाती है, फूल मुरझा जाते हैं, दीप बुझ जाते हैं, फिर भी उनसे उपजी छटा का आनंद मन में बचा रहता है। सौंदर्य का एक रहस्य उसकी क्षणभंगुरता में छिपा है। जो सदा नहीं रहता, वही कभी-कभी सबसे अधिक याद रह जाता है। एक छोटा-सा मिट्टी का दीया प्रकृति, श्रम और ऊर्जा का संसार समेटे रहता है। दीपक अंधेरे को पराजित करने की घोषणा नहीं करता। वह बस अपने हिस्से का प्रकाश देता है। शायद मनुष्य के लिए इससे बड़ी शिक्षा कोई नहीं कि अपनी छोटी-सी सामर्थ्य को व्यर्थ न जाने दे। दीपावली के साथ बाजार का विस्तार होता है। दुकानों की सजावट, नए वस्त्र, मिठाइयां और उपहार उत्सव को दृश्य वैभव देते हैं। बाजार इच्छाओं को पहचानता है और उन्हें नई वस्तुओं में बदलने की कला जानता है। वह बताता है कि किससे घर सुंदर होगा और कौन-सा उपहार संबंधों में मिठास बढ़ाएगा, पर वस्तु की चमक और जीवन की चमक एक नहीं होती। कोई महंगी वस्तु किसी संबंध की रिक्तता नहीं भर सकती, लेकिन दीपावली पर उपहार देने की परंपरा संबंधों की सुंदर भाषा है। कभी एक पुस्तक, घर में बनी मिठाई या हाथ से लिखा संदेश किसी बड़े उपहार से अधिक आत्मीय हो जाता है। उपहार यह कहने का विनम्र तरीका है कि दूसरा व्यक्ति हमारी स्मृति में उपस्थित है। समय ने परिवारों के रहने और मिलने के ढंग बदल दिए हैं। कई पीढ़ियां अब अलग-अलग नगरों और देशों में बसी हैं। डिजिटल माध्यमों ने दूरियों को छोटा किया है। मोबाइल की स्क्रीन पर चेहरे दिखाई देते हैं, शुभकामनाएं आती हैं, तस्वीरें साझा होती हैं। तकनीक ने संपर्क सहज बनाया है, लेकिन निकटता का अर्थ केवल एक-दूसरे को देख लेना नहीं है। किसी के पास बैठना, उसकी चुप्पी सुनना और साथ समय बिताना मनुष्य की ऐसी जरूरतें हैं, जिन्हें कोई उपकरण पूरा नहीं कर सकता। स्क्रीन चेहरा दिखा सकती है, उपस्थिति की ऊष्मा नहीं। उत्सव का सामाजिक अर्थ उन घरों की ओर देखने से खुलता है, जहां दीपावली की तैयारी सहज नहीं है। कहीं आर्थिक कठिनाई, कहीं बीमारी या अकेलापन है। किसी दूसरे के अंधेरे से अनजान रहकर अपनी रोशनी पर गर्व करना प्रकाश का कमजोर अर्थ है। किसी घर तक एक दीप पहुंचा देना कभी-कभी हजारों दीप जलाने से अधिक अर्थवान हो जाता है। प्रकृति के साथ हमारा संबंध दीपावली के अर्थ को नया विस्तार देता है। धुएं से भरी हवा और प्रदूषित परिवेश के बीच यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि उत्सव का आनंद प्रकृति की कीमत पर क्यों हो? परंपरा जीवन के साथ चलती है और समय से संवाद करती है। मिट्टी के दीपों को अपनाना, स्थानीय कारीगरों से वस्तुएं खरीदना तथा अनावश्यक शोर और धुएं से बचना उत्सव की आभा को अधिक संवेदनशील बनाना है। जिस धरती पर मनुष्य अपने उत्सव रचता है, उसकी सांसों का ध्यान रखना भी उत्सव की संस्कृति का हिस्सा है। दीपावली किसी के लिए घर लौटने की खुशी है, किसी के लिए बचपन की स्मृति, किसी के लिए धार्मिक आस्था और किसी के लिए नए आरंभ का संकेत। इन अलग-अलग अनुभूतियों के बीच एक साझा आकांक्षा है : जीवन में कुछ प्रकाशमय हो, संबंधों में सहजता लौटे और भविष्य के प्रति विश्वास बना रहे। उत्सव की सुंदरता उसकी इसी बहुलता में है। एक ही दीप की लौ अलग-अलग आंखों में अलग अर्थ लेकर उतरती है। क्या दीवाली पर हमने किसी पुराने संबंध को फिर से छुआ? किसी के श्रम को पहचाना? किसी अकेले व्यक्ति के लिए समय निकाला? दीपावली का स्थाई अर्थ शायद इसी बची हुई रोशनी में है। दीपक का प्रकाश सीमित होता है, लेकिन उससे जन्मी दृष्टि असीम हो सकती है। प्रकाश का सबसे सुंदर रूप वह नहीं, जो आंखों को चकाचौंध कर दे, बल्कि वह है जिसमें मनुष्य दूसरे मनुष्य को देख-समझ सके।

डिजिटल अर्थव्यवस्था की असली पूंजी है उपभोक्ताओं का भरोसा

डिजिटल साक्षरता को भी व्यापक जनअभियान का रूप देना होगा। लोगों को सरल भाषा में यह समझाना जरूरी है कि पैसा प्राप्त करने के लिए यूपीआई पिन डालने की आवश्यकता नहीं होती। कोई वास्तविक पुलिस अधिकारी वीडियो कॉल पर गिरफ्तारी की कार्रवाई नहीं करता।



भारत में आर्थिक लेनदेन की परंपरागत तस्वीर तेजी से बदल रही है। कभी बाजारों में खरीदारी के बाद जेब से नकदी निकालना, दुकानदारों का बही-खातों में हिसाब लिखना और घरों में धन को तिजोरियों में सुरक्षित रखना आम बात थी। अब यही काम मोबाइल फोन की एक छोटी-सी स्क्रीन से होने लगा है। चाय की दुकान से लेकर बड़े शोरूम तक भुगतान के लिए क्यूआर कोड का इस्तेमाल किया जा रहा है। दीपावली से पहले जारी आंकड़ों ने इस बदलाव की व्यापकता को सामने रखा। अक्टूबर 2026 में यूपीआई के माध्यम से देश में 2,547 करोड़ लेनदेन हुए और इनके जरिए कुल 31.53 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। पहली बार एक दिन में औसत लेनदेन का मूल्य एक लाख करोड़ रुपये से अधिक पहुंच गया। यह आंकड़ा केवल तकनीकी प्रगति का संकेत नहीं है, बल्कि भारतीय समाज की बदलती आर्थिक आदतों और डिजिटल व्यवस्था पर बढ़ते भरोसे को भी दर्शाता है। भारत में डिजिटल भुगतान की सफलता अचानक नहीं मिली है। इसके पीछे कई वर्षों की नीतिगत तैयारी, तकनीकी विकास और व्यापक स्तर पर लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने का प्रयास रहा है। जनधन खाते, आधार और मोबाइल फोन की त्रिमूर्ति ने इस परिवर्तन की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत अगस्त 2014 में हुई थी। जुलाई 2026 तक इसके तहत खोले गए खातों की संख्या 58.84 करोड़ से अधिक हो चुकी थी। इस पहल ने उन करोड़ों लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने में मदद की, जिनके लिए पहले बैंक तक पहुंचना भी आसान नहीं था। इसके बाद आधार आधारित पहचान, मोबाइल कनेक्टिविटी और डिजिटल भुगतान के साधनों ने वित्तीय सेवाओं को आम लोगों के लिए अधिक सुलभ बनाया।

यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ने इस पूरी व्यवस्था को नई गति दी। अगस्त 2016 में इसकी शुरुआत हुई तो पहले महीने केवल 90 हजार लेनदेन दर्ज किए गए थे। उस समय शायद ही किसी ने कल्पना की होगी कि कुछ वर्षों में यह प्रणाली दुनिया की सबसे बड़ी रियल-टाइम डिजिटल भुगतान व्यवस्थाओं में शामिल हो जाएगी। वित्त वर्ष 2025-26 में यूपीआई के माध्यम से लेनदेन की संख्या 24 हजार करोड़ से अधिक पहुंच गई और इनका कुल मूल्य लगभग 314 लाख करोड़ रुपये रहा। वित्त मंत्रालय के अनुसार, दुनिया में होने वाले रियल-टाइम डिजिटल भुगतानों में लगभग 49 प्रतिशत हिस्सेदारी यूपीआई की है। देश के कुल डिजिटल भुगतानों में भी इसकी भागीदारी 84 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है। यह उपलब्धि भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे की व्यापक स्वीकार्यता को रेखांकित करती है।

इस व्यवस्था का प्रभाव केवल बड़े शहरों, ऑनलाइन कारोबार या शिक्षित वर्ग तक सीमित नहीं रहा। डिजिटल भुगतान ने छोटे दुकानदारों, रेहड़ी-पटरी वालों, ऑटो चालकों और सामान्य ग्राहकों की रोजमर्रा की जिंदगी में भी जगह बना ली है। वित्त वर्ष 2025-26 में दुकानदारों को किए गए यूपीआई भुगतानों में 86 प्रतिशत लेनदेन 500 रुपये से कम के थे। इससे स्पष्ट होता है कि लोग छोटी-छोटी खरीदारी के लिए भी डिजिटल माध्यम अपना रहे हैं। अब सब्जी खरीदने, चाय पीने, ऑटो का किराया देने या किराने का सामान लेने के लिए नकदी रखना जरूरी नहीं रह गया है। ग्राहक मोबाइल से भुगतान करता है और दुकानदार के खाते में रकम पहुंच जाती है। इस प्रक्रिया से समय की बचत होती है और लेनदेन का रिकॉर्ड भी सुरक्षित रहता है।

छोटे कारोबारियों के लिए डिजिटल भुगतान का एक और महत्वपूर्ण लाभ है। पहले जिन दुकानदारों की आय और लेनदेन का कोई व्यवस्थित लिखित रिकॉर्ड नहीं होता था, अब उनके पास डिजिटल हिसाब उपलब्ध है। इस रिकॉर्ड के आधार पर वे अपनी आर्थिक गतिविधियों का प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं। इससे भविष्य में औपचारिक बैंकिंग सेवाओं और कर्ज तक उनकी पहुंच आसान हो सकती है। डिजिटल लेनदेन ने नकदी के प्रबंधन, छुट्टे पैसों की समस्या और भुगतान की अनिश्चितता को भी काफी हद तक कम किया है। यही वजह है कि यूपीआई अब केवल भुगतान का माध्यम नहीं, बल्कि छोटे कारोबार को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण साधन बनता जा रहा है।

डिजिटल क्रांति की इस सफलता के बीच सबसे बड़ी चिंता साइबर अपराधों की बढ़ती चुनौती है। जिस मोबाइल फोन ने भुगतान को आसान बनाया है, उसी के माध्यम से अपराधी लोगों की मेहनत की कमाई पर भी निशाना साध रहे हैं। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2025 में साइबर ठगी से जुड़ी 21.77 लाख शिकायतें दर्ज हुईं और लोगों को लगभग 19,813 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि वर्ष 2024 में दर्ज 22,849 करोड़ रुपये के नुकसान की तुलना में यह रकम कम रही, लेकिन इतनी बड़ी आर्थिक क्षति को सामान्य नहीं माना जा सकता। वर्ष 2025 में हुए कुल नुकसान का लगभग 77 प्रतिशत हिस्सा फर्जी निवेश योजनाओं और आठ प्रतिशत डिजिटल अरेस्ट जैसी ठगी से जुड़ा था। इन घटनाओं से स्पष्ट है कि साइबर अपराधी अब केवल तकनीकी खामियों का फायदा नहीं उठाते, बल्कि लोगों की भावनाओं, लालच और डर को भी अपना हथियार बनाते हैं। कभी अधिक मुनाफे का लालच देकर निवेश कराया जाता है तो कभी पुलिस, जांच एजेंसी या सरकारी अधिकारी बनकर लोगों को डराया जाता है। वीडियो कॉल के जरिए गिरफ्तारी का भय दिखाकर रकम वसूली जाती है। कई मामलों में ठग बैंक अधिकारी बनकर खाते की जानकारी हासिल कर लेते हैं। फर्जी लिंक, अनजान एप और ओटीपी साझा करने जैसी गलतियों से भी लोगों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए डिजिटल सुरक्षा का प्रश्न केवल तकनीकी व्यवस्था तक सीमित नहीं है। इसके लिए नागरिकों में जागरूकता और सतर्कता भी उतनी ही जरूरी है।

डिजिटल अर्थव्यवस्था के सामने दूसरी बड़ी चुनौती डिजिटल विभाजन की है। देश में अभी भी ऐसे अनेक क्षेत्र हैं, जहां इंटरनेट की गति और नेटवर्क की उपलब्धता भरोसेमंद नहीं है। बुजुर्गों, कम पढ़े-लिखे लोगों और तकनीक से अपरिचित नागरिकों के लिए डिजिटल भुगतान की प्रक्रिया कई बार कठिन हो जाती है। मोबाइल फोन के इस्तेमाल में थोड़ी-सी असावधानी भी उन्हें ठगी का शिकार बना सकती है। ऐसे में यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि डिजिटल व्यवस्था का विस्तार किसी वर्ग को पीछे छोड़कर न हो। भुगतान के पारंपरिक विकल्प भी उपलब्ध रहने चाहिए, ताकि तकनीकी परेशानी या नेटवर्क बाधित होने की स्थिति में आम लोगों को कठिनाई न उठानी पड़े।

डाटा की सुरक्षा और नागरिकों की निजता भी एक गंभीर विषय है। डिजिटल लेनदेन के दौरान लोगों की आर्थिक गतिविधियों से संबंधित बड़ी मात्रा में जानकारी विभिन्न प्रणालियों में दर्ज होती है। इस जानकारी का इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया जा रहा है और उसकी सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था है, यह सवाल महत्वपूर्ण है। डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के प्रावधानों का प्रभावी पालन सुनिश्चित करना आवश्यक है। कंपनियों और संस्थाओं को यह जिम्मेदारी समझनी होगी कि नागरिकों की निजी जानकारी उनकी अनुमति और निर्धारित नियमों के बिना किसी अन्य उद्देश्य के लिए इस्तेमाल न हो। डिजिटल व्यवस्था पर भरोसा तभी कायम रहेगा, जब लोगों को यह विश्वास होगा कि उनका पैसा ही नहीं, उनकी व्यक्तिगत जानकारी भी सुरक्षित है।

यूपीआई के आर्थिक मॉडल को लेकर भी संतुलित नीति की आवश्यकता है। फिलहाल आम उपभोक्ताओं के लिए अधिकांश सामान्य यूपीआई भुगतान मुफ्त हैं। लेकिन इस सेवा को संचालित करने वाले बैंकों और भुगतान कंपनियों को तकनीकी ढांचे, साइबर सुरक्षा, रखरखाव और नवाचार पर लगातार खर्च करना पड़ता है। यदि इन संस्थाओं के लिए पर्याप्त आर्थिक व्यवस्था नहीं होगी तो लंबे समय तक सेवा की गुणवत्ता और सुरक्षा बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसी संदर्भ में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई ने दुकानों पर दो हजार रुपये से अधिक के कुछ भुगतान पर 0.40 प्रतिशत, अधिकतम 300 रुपये तक शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे फिलहाल दीपावली के बाद तक टाल दिया गया। इस मुद्दे पर ऐसा रास्ता निकालना होगा, जिससे सेवा प्रदाताओं की आर्थिक जरूरतें भी पूरी हों और छोटे व्यापारियों तथा आम ग्राहकों पर अतिरिक्त बोझ भी न पड़े। शुल्क का दबाव अधिक हुआ तो कुछ दुकानदार डिजिटल भुगतान के बजाय फिर नकदी को प्राथमिकता दे सकते हैं।

डिजिटल भुगतान को सुरक्षित बनाने के लिए सबसे पहले साइबर ठगी की रकम को समय रहते रोकने की व्यवस्था मजबूत करनी होगी। ठगी की शिकायत मिलने के बाद बैंकों और संबंधित एजेंसियों के बीच तत्काल समन्वय जरूरी है। राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के बारे में अधिक से अधिक लोगों को जानकारी दी जानी चाहिए। ठगी का पता चलते ही शिकायत दर्ज कराने से रकम को आगे स्थानांतरित होने से रोकने की संभावना बढ़ सकती है। इसके साथ ही फर्जी सिम कार्ड, संदिग्ध बैंक खातों और म्यूल खातों पर कड़ी निगरानी जरूरी है। म्यूल खाते ऐसे बैंक खाते होते हैं, जिनका इस्तेमाल अपराधी ठगी से हासिल रकम को छिपाने या दूसरे खातों में भेजने के लिए करते हैं। कई बार भोले-भाले लोगों को कमीशन का लालच देकर उनके खाते इस काम में इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसे मामलों में जागरूकता और सख्त कार्रवाई दोनों जरूरी हैं।

डिजिटल साक्षरता को भी व्यापक जनअभियान का रूप देना होगा। लोगों को सरल भाषा में यह समझाना जरूरी है कि पैसा प्राप्त करने के लिए यूपीआई पिन डालने की आवश्यकता नहीं होती। कोई वास्तविक पुलिस अधिकारी वीडियो कॉल पर गिरफ्तारी की कार्रवाई नहीं करता। अनजान व्यक्ति को ओटीपी, पिन या बैंक संबंधी जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए। किसी भी निवेश योजना में पैसा लगाने से पहले उसकी प्रमाणिकता की जांच करनी चाहिए। स्कूलों, पंचायतों, बैंक शाखाओं और स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से ऐसे संदेश लगातार प्रसारित किए जा सकते हैं। खासकर वरिष्ठ नागरिकों और पहली बार डिजिटल भुगतान करने वाले लोगों को व्यावहारिक प्रशिक्षण देना उपयोगी होगा।

टेक्नॉलॉजी

फोन चोरी होते ही लॉक होगा मोबाइल, सुरक्षा के लिए पहले ही चालू कर लें ये तीन फीचर

आज के समय में स्मार्टफोन केवल बातचीत का साधन नहीं रह गया है, बल्कि इसमें बैंकिंग से लेकर निजी तस्वीरों, दस्तावेजों, ईमेल और सोशल मीडिया खातों तक की महत्वपूर्ण जानकारियां मौजूद रहती हैं। ऐसे में मोबाइल फोन चोरी या छिन जाने पर सबसे बड़ी चिंता उसके खोने की नहीं, बल्कि उसमें सुरक्षित निजी डाटा के दुरुपयोग की होती है। कई बार फोन गलत हाथों में पहुंचने के बाद उसका इस्तेमाल करके बैंक खातों, डिजिटल भुगतान और अन्य निजी सेवाओं तक पहुंचने की कोशिश की जाती है। हालांकि एंड्रॉयड स्मार्टफोन में मौजूद कुछ इन-बिल्ट सुरक्षा सुविधाएं ऐसी परिस्थितियों में नुकसान की आशंका कम कर सकती हैं। इसके लिए उपयोगकर्ताओं को फोन चोरी होने का इंतजार करने के बजाय पहले ही तीन महत्वपूर्ण सुरक्षा विकल्प सक्रिय कर लेने चाहिए।

एंड्रॉयड फोन में उपलब्ध पहला महत्वपूर्ण फीचर 'थेफ्ट डिटेक्शन लॉक' है। यह सुविधा फोन छीनकर भागने जैसी स्थिति को पहचानने के लिए बनाई गई है। यदि फोन को अचानक झपटकर ले जाने जैसी गतिविधि का पता चलता है तो यह स्क्रीन को अपने आप लॉक कर सकता है। इससे चोर के लिए फोन का तत्काल इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता है। इसके साथ ही 'ऑफलाइन डिवाइस लॉक' का विकल्प भी काफी उपयोगी है। यदि कोई व्यक्ति चोरी किए गए फोन को इंटरनेट से डिस्कनेक्ट कर देता है तो यह सुविधा निर्धारित परिस्थितियों में स्क्रीन को लॉक कर सकती है। इन विकल्पों को चालू करने के लिए फोन की सेटिंग में जाकर 'थेफ्ट प्रोटेक्शन' सेक्शन खोलें। यहां 'थेफ्ट डिटेक्शन लॉक' और 'ऑफलाइन डिवाइस लॉक' को सक्रिय कर दें। हालांकि इन सुविधाओं की उपलब्धता और काम करने का तरीका फोन के मॉडल तथा एंड्रॉयड संस्करण के अनुसार अलग-अलग हो सकता है।

दूसरा उपयोगी विकल्प 'रिमोट लॉक' है। इसकी मदद से फोन अपने पास नहीं होने पर भी किसी दूसरे डिवाइस के माध्यम से उसकी स्क्रीन लॉक की जा सकती है। इसके लिए सबसे पहले अपने एंड्रॉयड फोन की सेटिंग में जाकर थेफ्ट प्रोटेक्शन के अंतर्गत रिमोट लॉक सुविधा को सक्रिय करना जरूरी है। यदि भविष्य में फोन चोरी हो जाता है तो किसी अन्य मोबाइल या कंप्यूटर के ब्राउजर में android.com/lock खोलकर अपने फोन नंबर की मदद से लॉक करने की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। इस सुविधा के लिए गूगल अकाउंट से साइन-इन करना जरूरी नहीं होता, लेकिन पहले से रिमोट लॉक सक्रिय होना और फोन का इंटरनेट से जुड़ा होना आवश्यक है। यदि चोरी के समय फोन ऑफलाइन है तो लॉक का आदेश उस समय लागू होगा, जब डिवाइस दोबारा ऑनलाइन आएगा। इसलिए इस सुविधा को पहले से चालू रखना बेहद जरूरी है।

तीसरा और महत्वपूर्ण सुरक्षा विकल्प 'फाइंड माय डिवाइस' है। यह सुविधा फोन खोने या चोरी होने की स्थिति में उसकी लोकेशन पता करने, स्क्रीन लॉक करने और जरूरत पड़ने पर उसमें मौजूद डाटा मिटाने में मदद करती है। एंड्रॉयड डिवाइस में गूगल अकाउंट जोड़ने पर यह सुविधा सामान्यतः डिफॉल्ट रूप से सक्रिय रहती है, फिर भी उपयोगकर्ताओं को अपनी सेटिंग में जाकर इसकी स्थिति जरूर जांच लेनी चाहिए। इसके लिए फोन की सेटिंग में 'फाइंड माय डिवाइस' विकल्प खोजें और सुनिश्चित करें कि यह चालू है। फोन खोने के बाद किसी दूसरे एंड्रॉयड डिवाइस में इसका एप खोलकर या ब्राउजर के माध्यम से संबंधित सेवा का इस्तेमाल किया जा सकता है। अपने गूगल अकाउंट से साइन-इन करने के बाद उस डिवाइस को चुनें, जिसे आप खोज रहे हैं। उपलब्ध जानकारी के आधार पर फोन की लोकेशन मैप पर दिखाई दे सकती है। इसके अलावा फोन को सुरक्षित करने और आवश्यकता पड़ने पर उसका डाटा मिटाने के विकल्प भी मिलते हैं।

हालांकि फोन की लोकेशन देखने और उसे सुरक्षित करने के लिए कुछ शर्तें पूरी होना जरूरी है। डिवाइस चालू होना चाहिए, उसमें गूगल अकाउंट साइन-इन होना चाहिए और संबंधित सुरक्षा सुविधा सक्रिय होनी चाहिए। लोकेशन की जानकारी उपलब्ध होने के लिए नेटवर्क और डिवाइस की अन्य निर्धारित स्थितियां भी महत्वपूर्ण हैं। कुछ परिस्थितियों में ऑफलाइन फाइंडिंग की सुविधा पहले से उपलब्ध होने पर आखिरी ज्ञात लोकेशन या अन्य नेटवर्क आधारित जानकारी मिल सकती है। इसलिए फोन की सुरक्षा सेटिंग्स को समय रहते जांचना बेहतर है। इन तीनों सुविधाओं के अलावा मोबाइल उपयोगकर्ताओं को कुछ बुनियादी सावधानियां भी अपनानी चाहिए। फोन में मजबूत स्क्रीन लॉक और अलग-अलग खातों के लिए सुरक्षित पासवर्ड रखें। बैंकिंग एप और यूपीआई से जुड़ी जानकारी किसी अनजान व्यक्ति के साथ साझा न करें। ओटीपी, पिन और पासवर्ड मांगने वाले फोन कॉल या संदेशों से सावधान रहें। मोबाइल चोरी होने पर तुरंत अपने दूरसंचार सेवा प्रदाता से सिम बंद कराने और बैंक से संपर्क करने की कार्रवाई करें। जरूरत पड़ने पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं और साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 पर भी सूचना दें। स्मार्टफोन की सुरक्षा केवल महंगे मोबाइल खरीदने या उसमें पासवर्ड लगाने तक सीमित नहीं है। असली सुरक्षा इस बात पर निर्भर करती है कि उपयोगकर्ता उपलब्ध तकनीकी सुविधाओं का सही इस्तेमाल कितना करते हैं।

विचार प्रवाह

सैनिक स्कूलों में दाखिले का मौका, AISSEE 2027 के लिए आवेदन शुरू

सैनिक स्कूलों में पढ़ाई का सपना देख रहे विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा (एआईएसएसई) 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस परीक्षा के माध्यम से देश के सैनिक स्कूलों में कक्षा छह और कक्षा नौ में प्रवेश दिया जाएगा। इच्छुक अभिभावक एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपने बच्चों का आवेदन करा सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि दो दिसंबर 2026 निर्धारित की गई है। आवेदन के दौरान किसी प्रकार की गलती होने पर उसे सुधारने के लिए छह से नौ दिसंबर 2026 तक संशोधन का अवसर दिया जाएगा।

एनटीए की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, एआईएसएसई 2027 की प्रवेश परीक्षा 31 जनवरी 2027 को आयोजित की जानी है। परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों को परीक्षा शहर की जानकारी देने के लिए सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी की जाएगी। निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक सिटी स्लिप 11 जनवरी 2027 को उपलब्ध कराई जाएगी, जबकि प्रवेश पत्र 25 जनवरी 2027 को जारी किए जाने की जानकारी दी गई है। सिटी स्लिप के माध्यम से अभिभावक यह जान सकेंगे कि उनके बच्चे की परीक्षा किस शहर में आयोजित होगी। हालांकि यह परीक्षा केंद्र का अंतिम पता नहीं होती। परीक्षा केंद्र से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रवेश पत्र में दी जाएगी। इस प्रवेश परीक्षा में वे अभिभावक अपने बच्चों के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो उन्हें सैनिक स्कूलों में कक्षा छह अथवा कक्षा नौ में दाखिला दिलाना चाहते हैं। आवेदन करने से पहले विद्यार्थियों की आयु और शैक्षणिक योग्यता से संबंधित निर्धारित शर्तों को ध्यान से समझना जरूरी है। कक्षा के अनुसार पात्रता के नियम अलग-अलग होते हैं। इसलिए अभिभावकों को आवेदन करने से पहले आधिकारिक सूचना पुस्तिका में दी गई आयु सीमा, जन्मतिथि और अन्य आवश्यक योग्यताओं की जांच कर लेनी चाहिए। गलत जानकारी के आधार पर आवेदन करने से आगे चलकर प्रवेश प्रक्रिया में परेशानी हो सकती है। आवेदन के साथ निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करना भी अनिवार्य होगा। सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए पंजीकरण शुल्क 850 रुपये रखा गया है, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को 700 रुपये शुल्क देना होगा। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकेगा। अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि आवेदन पूरा करने के बाद उसकी जानकारी और भुगतान की रसीद सुरक्षित रख लें, ताकि भविष्य में किसी तरह की परेशानी होने पर उसका उपयोग किया जा सके।

परीक्षा के पैटर्न की बात करें तो कक्षा छह और कक्षा नौ के लिए प्रश्नों की संख्या, कुल अंक और परीक्षा की अवधि अलग-अलग निर्धारित की गई है। कक्षा छह की प्रवेश परीक्षा में विद्यार्थियों से कुल 125 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। यह परीक्षा 300 अंकों की होगी और इसके लिए 150 मिनट का समय मिलेगा। वहीं कक्षा नौ की परीक्षा में कुल 150 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। यह परीक्षा 400 अंकों की होगी और अभ्यर्थियों को इसे पूरा करने के लिए 180 मिनट का समय दिया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को अपने पाठ्यक्रम और प्रश्नों के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी चाहिए। निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार कक्षा छह की परीक्षा दोपहर दो बजे से शाम 4:30 बजे तक आयोजित होगी। वहीं कक्षा नौ के विद्यार्थियों की परीक्षा दोपहर दो बजे से शाम पांच बजे तक चलेगी। दोनों कक्षाओं के लिए परीक्षा एक ही दिन आयोजित की जाएगी। ऐसे में अभिभावकों को परीक्षा से पहले बच्चों की तैयारी के साथ-साथ प्रवेश पत्र, परीक्षा केंद्र और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी भी जुटा लेनी चाहिए।

सैनिक स्कूलों में प्रवेश पाने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए यह परीक्षा एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन विद्यालयों में विद्यार्थियों को शैक्षणिक शिक्षा के साथ अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, शारीरिक गतिविधियों और व्यक्तित्व विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। इसलिए दाखिले के लिए प्रतिस्पर्धा को देखते हुए अभ्यर्थियों को नियमित अभ्यास और समय प्रबंधन के साथ तैयारी करनी चाहिए। आवेदन की अंतिम तिथि का इंतजार करने के बजाय समय रहते फॉर्म भरना बेहतर रहेगा। अभिभावकों को आवेदन से जुड़ी किसी भी जानकारी, पात्रता और परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव के लिए एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी अधिसूचना को ही अंतिम आधार मानना चाहिए।

फैक्ट ऑफ द डे

पत्रकारिता, इतिहास और शिक्षा के क्षेत्र में अमिट छाप छोड़ने वाले इन्द्र विद्यावाचस्पति

भारतीय हिंदी पत्रकारिता और साहित्य के इतिहास में कुछ ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं, जिन्होंने अपनी लेखनी को केवल विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं बनाया, बल्कि उसे समाज के जागरण, राष्ट्रीय चेतना और सांस्कृतिक पुनर्निर्माण का साधन भी बनाया। इन्द्र विद्यावाचस्पति ऐसे ही बहुआयामी व्यक्तित्व थे। वे कुशल पत्रकार, गंभीर चिंतक, इतिहास के गहन अध्येता और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले कर्मयोगी थे। उनका जीवन पत्रकारिता की निर्भीकता, साहित्य की गंभीरता और भारतीय शिक्षा व्यवस्था के प्रति समर्पण का उदाहरण प्रस्तुत करता है। उन्होंने अपने लेखन और कार्यों के माध्यम से हिंदी भाषा को प्रतिष्ठा दिलाने के साथ-साथ भारतीय इतिहास और संस्कृति के अनेक महत्वपूर्ण पक्षों को जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास किया।

इन्द्र विद्यावाचस्पति का जन्म 9 नवंबर 1889 को पंजाब के जालंधर जिले के नवांशहर में हुआ था। वे आर्य समाज के प्रमुख नेता, समाज सुधारक और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े महान व्यक्तित्व स्वामी श्रद्धानन्द के पुत्र थे। घर में धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय विचारों का वातावरण था। ऐसे परिवेश ने उनके व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बचपन से ही उन्हें भारतीय संस्कृति, वैदिक विचारधारा और समाज सुधार के कार्यों के प्रति रुचि विकसित करने का अवसर मिला। पिता के विचारों और सामाजिक गतिविधियों का प्रभाव उनके जीवन पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उन्होंने अपनी शिक्षा



गुरुकुल कांगड़ी में प्राप्त की। गुरुकुल का वातावरण अनुशासन, भारतीय ज्ञान परंपरा और राष्ट्रभाषा के प्रति सम्मान से परिपूर्ण था। इसी वातावरण में उनके भीतर अध्ययन, लेखन और सामाजिक दायित्वों के प्रति गंभीरता विकसित हुई।

विद्यार्थी जीवन में ही उन्हें पत्रकारिता से जुड़ने का अवसर मिला। गुरुकुल में अध्ययन के दौरान उन्हें 'सद्धर्म प्रचारक' के संपादन का दायित्व सौंपा गया। यह उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। संपादन के कार्य ने उनकी लेखन क्षमता को दिशा दी और उन्हें समाज, धर्म, राजनीति तथा शिक्षा से जुड़े विषयों पर विचार व्यक्त करने का अवसर मिला। धीरे-धीरे पत्रकारिता उनके जीवन का प्रमुख कार्यक्षेत्र बन गई। उन्होंने सम

मंदिरों में दर्शन से नागरिकों के स्नेहमिलन तक, नववर्ष पर जनता के बीच रहेंगे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल



गांधीनगर। गुजराती नववर्ष विक्रम संवत 2083 का आगाज गुजरात में धार्मिक आस्था, सामाजिक मेल-मिलाप और उत्सवी उल्लास के साथ होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल 10 नवंबर को गांधीनगर और अहमदाबाद में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होकर नागरिकों के साथ नववर्ष की खुशियां साझा करेंगे। मुख्यमंत्री का दिन मंदिरों में दर्शन-पूजन से शुरू होगा और फिर आम नागरिकों, राज्यपाल आचार्य देवव्रत, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तथा उनके परिवारों से मुलाकात के साथ आगे बढ़ेगा। निर्धारित कार्यक्रमों के तहत वे अलग-अलग स्थानों पर आयोजित स्नेहमिलन समारोहों में पहुंचकर लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं देंगे और उनके साथ उत्सव की खुशियां बांटेंगे।

मुख्यमंत्री का पहला कार्यक्रम सुबह सात बजे गांधीनगर स्थित पंचदेव मंदिर में होगा। यहां वे दर्शन-पूजन कर नए वर्ष की शुरुआत करेंगे। इसके बाद सुबह 7:30 बजे वे अडालज स्थित त्रिमंदिर पहुंचेंगे और वहां पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। धार्मिक स्थलों पर दर्शन के बाद मुख्यमंत्री का कार्यक्रम आम नागरिकों के बीच पहुंचने का रहेगा। सुबह आठ बजे गांधीनगर के मंत्रिमंडल आवास परिसर स्थित कम्युनिटी सेंटर में नववर्ष स्नेहमिलन समारोह आयोजित किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री नागरिकों से मुलाकात करेंगे और उन्हें नववर्ष की शुभकामनाएं देंगे।

गांधीनगर में निर्धारित कार्यक्रमों के क्रम में मुख्यमंत्री सुबह 8:50 बजे राजभवन पहुंचेंगे। यहां वे गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मुलाकात कर उन्हें विक्रम संवत 2083 के शुभारंभ की बधाई देंगे। इस मुलाकात के दौरान दोनों के बीच नववर्ष की शुभकामनाओं का आदान-प्रदान होगा। राज्यपाल से भेंट के बाद मुख्यमंत्री अहमदाबाद के लिए रवाना होंगे, जहां उनके कई कार्यक्रम निर्धारित हैं।

अहमदाबाद में मुख्यमंत्री का पहला पड़ाव सुबह दस बजे ऐतिहासिक भद्रकाली माता मंदिर होगा। यहां वे माता के दर्शन कर पूजा-अर्चना करेंगे। भद्रकाली मंदिर शहर के प्रमुख धार्मिक स्थलों में शामिल है और गुजराती नववर्ष के अवसर पर यहां श्रद्धालुओं की विशेष आवाजाही रहती है। मंदिर में दर्शन के बाद मुख्यमंत्री सुबह 10:30 बजे शाहीबाग स्थित एनेक्सी स्टेट गेस्ट हाउस पहुंचेंगे। यहां आयोजित नववर्ष स्नेहमिलन कार्यक्रम में वे आम नागरिकों से मुलाकात कर उन्हें नए साल की शुभकामनाएं देंगे। इस आयोजन के जरिए मुख्यमंत्री को समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों से सीधे संवाद और उत्सव की खुशियां साझा करने का अवसर मिलेगा।

मुख्यमंत्री के नववर्ष कार्यक्रमों में पुलिस विभाग के अधिकारियों और उनके परिवारों के साथ मुलाकात भी शामिल है। इसके लिए सुबह 11:45 बजे शाहीबाग के डफनाला स्थित पुलिस ऑफिसर्स मेस में विशेष समारोह आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और उनके परिजनों से मिलेंगे तथा उन्हें नववर्ष की बधाई देंगे। पुलिस विभाग के अधिकारियों और उनके परिवारों के साथ यह स्नेहमिलन कार्यक्रम नए वर्ष के अवसर पर उनके प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करने का अवसर होगा।

इस प्रकार मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का 10 नवंबर का कार्यक्रम धार्मिक आस्था, सामाजिक संवाद और प्रशासनिक परिवार के साथ आत्मीय मुलाकातों पर केंद्रित रहेगा। सुबह मंदिरों में दर्शन से शुरू होने वाला उनका दिन गांधीनगर और अहमदाबाद के विभिन्न स्नेहमिलन समारोहों के साथ आगे बढ़ेगा। राज्यपाल से मुलाकात के साथ-साथ आम नागरिकों और पुलिस अधिकारियों के बीच पहुंचकर वे नववर्ष के उत्सव में सहभागी बनेंगे।

गुजरात में दीपावली के अगले दिन मनाया जाने वाला बेस्टु वर्ष यानी गुजराती नववर्ष परंपरागत रूप से नई शुरुआत, शुभकामनाओं और आपसी मेल-मिलाप का पर्व माना जाता है। इस दिन लोग मंदिरों में दर्शन करते हैं, परिवार और परिचितों से मिलते हैं तथा एक-दूसरे को 'साल मुबारक' कहकर नए वर्ष की बधाई देते हैं। व्यापारी वर्ग के लिए भी यह दिन विशेष महत्व रखता है, क्योंकि नए बही-खातों और कारोबारी वर्ष की शुरुआत से जुड़ी परंपराएं निभाई जाती हैं। विक्रम संवत 2083 के आगमन पर मुख्यमंत्री के निर्धारित कार्यक्रम भी इसी सामाजिक और सांस्कृतिक परंपरा के अनुरूप रखे गए हैं।

नववर्ष के पहले दिन मुख्यमंत्री का दोनों प्रमुख शहरों में नागरिकों के बीच पहुंचना राज्य सरकार और आम लोगों के बीच संवाद का अवसर भी बनेगा। धार्मिक स्थलों पर दर्शन के बाद सार्वजनिक स्नेहमिलन कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी से उत्सव का संदेश व्यापक स्तर पर साझा होगा। गांधीनगर से अहमदाबाद तक निर्धारित इन कार्यक्रमों के माध्यम से मुख्यमंत्री नागरिकों, राज्यपाल और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नववर्ष की खुशियां बांटेंगे।

सोशल मीडिया के जरिए नाबालिगों को आतंकी नेटवर्क से जोड़ने की कोशिश, पाकिस्तानी हैंडलर के तार जुड़े



श्रीगंगानगर। भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में सोशल मीडिया के माध्यम से कथित आतंकी नेटवर्क तैयार करने की कोशिश का मामला सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियों में हलचल मच गई है। पुलिस को जानकारी मिली है कि जिले के तीन नाबालिग युवक पाकिस्तान में बैठे कथित हैंडलर शहजाद भट्टी के संपर्क में थे। शुरुआती जांच में आशंका जताई गई है कि सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के जरिए स्थानीय युवाओं का ब्रेनवॉश कर उन्हें भारत विरोधी गतिविधियों से जोड़ने तथा स्लीपर सेल तैयार करने का प्रयास किया जा रहा था। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए रायसिंहनगर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस को इस कथित नेटवर्क के बारे में जानकारी आसूचना अधिकारी के माध्यम से मिली थी। प्राप्त सूचना के अनुसार, श्रीगंगानगर जिले के तीन नाबालिग युवक सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर शहजाद भट्टी के संपर्क में थे। बताया गया है कि इन युवकों से टेलीग्राम और अन्य मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपर्क बनाए जाने की आशंका है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इन नाबालिगों का संबंधित व्यक्ति से संपर्क कब और कैसे शुरू हुआ तथा बातचीत के दौरान उन्हें किस तरह के संदेश और निर्देश दिए गए।

प्राथमिकी में कांस्टेबल अशोक कुमार के बयान के आधार पर आरोप लगाया गया है कि शहजाद भट्टी कथित तौर पर टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर अलग-अलग ग्रुप बनाकर भारतीय युवाओं को अपने संपर्क में लाने का प्रयास करता है। इन डिजिटल माध्यमों के जरिए युवाओं को चिह्नित कर उनसे संपर्क बढ़ाने और धीरे-धीरे उन्हें अपने नेटवर्क का हिस्सा बनाने की आशंका जताई गई है। पुलिस को संदेह है कि इस प्रक्रिया के तहत युवाओं को भारत विरोधी गतिविधियों के लिए तैयार करने की कोशिश की जा सकती थी। हालांकि, नाबालिगों की वास्तविक भूमिका और कथित नेटवर्क से उनके जुड़ाव की प्रकृति जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

पुलिस की प्राथमिकी में कुछ पाकिस्तानी मोबाइल नंबरों का भी उल्लेख किया गया है, जिनके माध्यम से संपर्क किए जाने की जानकारी सामने आई है। इसके अलावा टेलीग्राम पर @Ranahunain333 नाम की आईडी और सिग्नल एप पर RANA BHAI 3333 नाम से संचालित आईडी का जिक्र किया गया है। जांच अधिकारी अब इन मोबाइल नंबरों और सोशल मीडिया खातों की डिजिटल गतिविधियों की पड़ताल कर रहे हैं। यह जानने की कोशिश की जा रही है कि इन आईडी का संचालन कौन कर रहा था, इनके जरिए किन लोगों से बातचीत की गई और स्थानीय युवाओं को कथित नेटवर्क से जोड़ने के लिए किस तरह की रणनीति अपनाई गई। जांच एजेंसियों को आशंका है कि सीमावर्ती क्षेत्र के युवाओं तक पहुंच बनाकर उन्हें नेटवर्क का हिस्सा बनाने की कोशिश की जा रही थी। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि तीनों नाबालिगों का संपर्क केवल सोशल मीडिया तक सीमित था या उन्हें किसी तरह की गतिविधि के लिए प्रेरित भी किया गया था। इसके साथ ही यह जांच भी की जा रही है कि क्या जिले में अन्य युवक भी इस तरह के संपर्क में आए हैं। डिजिटल साक्ष्यों, मोबाइल नंबरों और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध जानकारियों के आधार पर पूरे संपर्क तंत्र की कड़ियां जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

इस मामले की प्राथमिकी में हरियाणा और राजस्थान में सामने आए कुछ पुराने घटनाक्रमों का भी उल्लेख किया गया है। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, 13 मार्च 2026 को हरियाणा के अंबाला जिले के बराड़ा थाना क्षेत्र में शहजाद भट्टी के एक कथित भारतीय सहयोगी को गिरफ्तार किया गया था। प्राथमिकी में उसके कब्जे से विस्फोटक सामग्री बरामद होने का भी जिक्र है। जांच एजेंसियां इस घटनाक्रम को कथित नेटवर्क की गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण मान रही हैं और यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि गिरफ्तार व्यक्ति के संपर्क किन लोगों से थे। इसके अलावा प्राथमिकी में हनुमानगढ़ जिले में शहजाद भट्टी के एक कथित सहयोगी के पहुंचने और वहां रेकी से जुड़ी गतिविधियों में शामिल रहने का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, 24 मार्च 2026 को सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क किए जाने और हनुमानगढ़ जिले में कथित आतंकी मॉड्यूल तथा सहयोगी तैयार करने संबंधी गतिविधियों का भी जिक्र सामने आया था।

मुहूर्त कारोबार में शुरुआती तेजी के बाद फिसला सोना-चांदी, निवेशकों ने की मुनाफावसूली

नई दिल्ली। दीपावली के अवसर पर रविवार को कमोडिटी बाजार में आयोजित विशेष मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव का दौर देखने को मिला। शुभ मुहूर्त में कारोबार की शुरुआत तेजी के साथ हुई और निवेशकों की खरीदारी के चलते दोनों कीमती धातुओं के वायदा भाव में अच्छी बढ़त दर्ज की गई। हालांकि, शुरुआती तेजी अधिक समय तक कायम नहीं रह सकी। ऊंचे स्तर पर कारोबारियों की ओर से मुनाफावसूली शुरू होने के कारण सोने और चांदी की चमक कारोबार के अंतिम चरण में फीकी पड़ गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर दिसंबर डिलीवरी का सोना शुरुआती कारोबार में 500 रुपये से अधिक चढ़ गया था, जबकि चांदी के भाव में भी प्रति किलोग्राम करीब 550 रुपये तक की तेजी आई। लेकिन सत्र समाप्त होने तक दोनों धातुएं गिरावट के साथ बंद हुईं। एमसीएक्स पर दिसंबर डिलीवरी का सोना कारोबार के अंत में 32 रुपये की गिरावट के साथ 1,42,520 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। इसी तरह चांदी का वायदा भाव 89 रुपये टूटकर 1,85,011 रुपये प्रति किलोग्राम रह गया। कारोबार की शुरुआत में दिखाई दी तेजी के मुकाबले अंतिम भाव में आई गिरावट से साफ हुआ कि निवेशकों ने ऊंचे स्तर पर मुनाफा निकालने को प्राथमिकता दी। हालांकि, गिरावट बहुत अधिक नहीं रही, लेकिन मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान शुरुआती उत्साह के बाद बाजार का कमजोर पड़ना निवेशकों के लिए अहम संकेत माना जा रहा है।

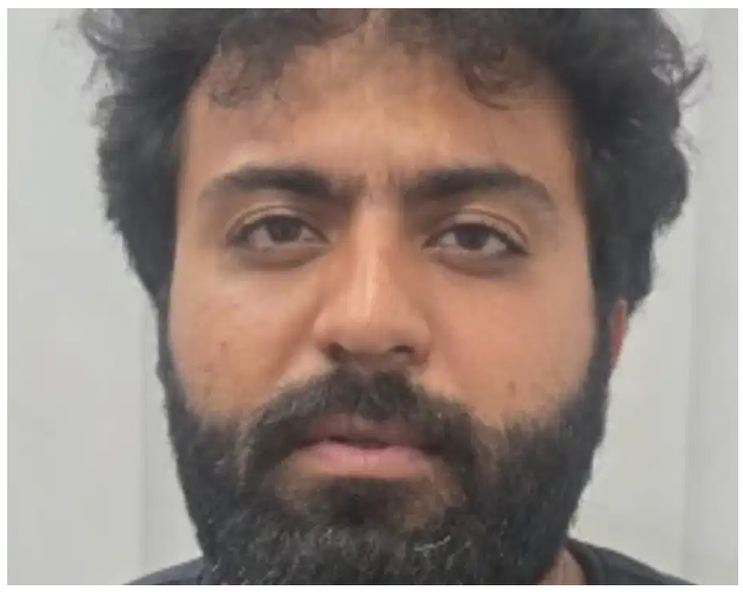
इससे पहले शुक्रवार को धनतेरस के अवसर पर भी सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी। एमसीएक्स पर सोना 1,731 रुपये टूटकर 1,42,167 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। इसके विपरीत चांदी में मामूली मजबूती देखने को मिली थी और इसका भाव 190 रुपये बढ़कर 1,84,787 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया था। लगातार दो कारोबारी सत्रों में सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव ने यह संकेत दिया है कि वैश्विक परिस्थितियों और निवेशकों की कारोबारी रणनीति का असर कीमती धातुओं पर बना हुआ है। त्योहारों के दौरान पारंपरिक रूप से सोने-चांदी की खरीदारी बढ़ती है, लेकिन वायदा बाजार में कीमतों की दिशा केवल घरेलू मांग से तय नहीं होती। अंतरराष्ट्रीय बाजार, डॉलर की स्थिति, ब्याज दरों की संभावनाएं और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

पिछले सप्ताह घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सोने तथा चांदी की कीमतों में सुधार देखने को मिला। सप्ताह के दौरान दोनों धातुओं ने अच्छी बढ़त हासिल की, लेकिन आने वाले दिनों में तेजी का यह रुख बरकरार रहने को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। बाजार के जानकारों के अनुसार, आगामी सप्ताह में महंगाई से जुड़े नए आंकड़े, कच्चे तेल की कीमतों में होने वाला उतार-चढ़ाव और अमेरिका-ईरान के बीच संघर्ष से जुड़े घटनाक्रम कीमती धातुओं की चाल को प्रभावित कर सकते हैं। इन घटनाओं से वैश्विक निवेशकों की जोखिम लेने की क्षमता और सुरक्षित निवेश के विकल्पों के प्रति रुझान में बदलाव आ सकता है। ऐसे में सोने और चांदी के भाव में तेजी या गिरावट दोनों की संभावना बनी रहेगी। सप्ताहभर के आंकड़ों पर नजर डालें तो एमसीएक्स पर दिसंबर डिलीवरी का सोना 3,682 रुपये यानी करीब तीन प्रतिशत मजबूत हुआ। इस बढ़त के साथ सोने का वायदा भाव लगभग 1.42 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया। इसी अवधि में चांदी ने सोने से कुछ अधिक मजबूती दिखाई। चांदी का वायदा भाव 5,655 रुपये यानी करीब 3.15 प्रतिशत उछलकर 1.84 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गया। इससे स्पष्ट है कि हालिया गिरावट के बावजूद सप्ताह के आधार पर दोनों कीमती धातुओं में खरीदारी का रुझान बना रहा। हालांकि, अलग-अलग कारोबारी सत्रों में आई तेजी और गिरावट ने बाजार को अस्थिर बनाए रखा। सोने की मौजूदा कीमतों की तुलना इस साल जनवरी में बने रिकॉर्ड स्तर से करें तो इसमें काफी अंतर दिखाई देता है। जनवरी में सोने का भाव करीब 1.80 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया था। उस समय वैश्विक अनिश्चितता और सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की बढ़ती मांग ने कीमतों को ऊंचाई दी थी। लेकिन इसके बाद बाजार की परिस्थितियां बदलीं और सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। रिकॉर्ड स्तर से नीचे आने के पीछे अमेरिकी डॉलर की मजबूती, बॉन्ड प्रतिफल में बढ़ोतरी और अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद कमजोर पड़ने जैसे कारण प्रमुख रहे।

आमतौर पर जब अमेरिकी डॉलर मजबूत होता है तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर में कारोबार करने वाले सोने की कीमतों पर दबाव पड़ सकता है। वहीं, बॉन्ड प्रतिफल में बढ़ोतरी होने से निवेशकों के लिए ब्याज देने वाले निवेश विकल्प अधिक आकर्षक हो जाते हैं। सोना स्वयं कोई ब्याज या नियमित आय नहीं देता, इसलिए बॉन्ड से मिलने वाला बेहतर प्रतिफल सोने की मांग को प्रभावित कर सकता है। इसके अतिरिक्त, जब बाजार में सोने की कीमतें तेजी से बढ़ती हैं तो निवेशक अपने निवेश पर मुनाफा सुरक्षित करने के लिए बिकवाली भी करते हैं। हाल के दिनों में हुई मुनाफावसूली ने भी सोने की कीमतों में गिरावट को बढ़ाने में भूमिका निभाई।

चांदी के बाजार में भी इसी तरह वैश्विक परिस्थितियों और निवेशकों की गतिविधियों का असर देखने को मिल रहा है। चांदी का उपयोग निवेश के साथ-साथ औद्योगिक क्षेत्रों में भी होता है। इसलिए इसकी कीमतों पर वैश्विक आर्थिक गतिविधियों, औद्योगिक मांग और निवेशकों की खरीद-बिक्री का संयुक्त प्रभाव पड़ता है। सप्ताह के दौरान चांदी में सोने से अधिक प्रतिशत की बढ़त दर्ज होना बाजार में इसकी मजबूत गतिविधि को दर्शाता है, लेकिन मुहूर्त ट्रेडिंग के अंत में आई गिरावट बताती है कि ऊंचे भाव पर निवेशक सतर्क बने हुए हैं। आने वाला सप्ताह सोने और चांदी के बाजार के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। महंगाई के आंकड़ों से यह संकेत मिलेगा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में कीमतों का दबाव किस दिशा में बढ़ रहा है।

जेल में रोज लगती रही हाजिरी, पांच दिन थाईलैंड घूमकर लौट आया उम्रकैद का कैदी, खुली जेल की व्यवस्था पर उठे सवाल



जयपुर। राजस्थान की जेल व्यवस्था और खासकर खुली जेलों में कैदियों की निगरानी को लेकर एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जयपुर के चर्चित दुष्यंत हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहा श्रीगंगानगर निवासी दीक्षांत कामरा कथित तौर पर पांच दिनों तक थाईलैंड घूमकर वापस आ गया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस दौरान खुली जेल में उसकी नियमित हाजिरी दर्ज होती रही। एक तरफ जेल के रिकॉर्ड में उसकी मौजूदगी दिखाई देती रही तो दूसरी तरफ उसके पासपोर्ट पर विदेश यात्रा से जुड़ी एंट्री मिलने की जानकारी सामने आई है। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर एक उम्रकैद का कैदी जेल की निगरानी व्यवस्था को चकमा देकर विदेश कैसे पहुंच गया? उसकी गैरमौजूदगी में हाजिरी किसने दर्ज की और क्या इस पूरे मामले में किसी स्तर पर लापरवाही या मिलीभगत हुई? मामला सामने आने के बाद राजस्थान की खुली जेलों की निगरानी व्यवस्था कठघरे में आ गई है।

जानकारी के अनुसार, दीक्षांत कामरा 9 अक्टूबर 2025 से 13 अक्टूबर 2025 तक थाईलैंड में रहा था। इस अवधि के दौरान उसके पासपोर्ट पर विदेश यात्रा से संबंधित एंट्री दर्ज होने की बात सामने आई है। आरोप है कि विदेश में रहने के बावजूद नरसिंहपुर खुली जेल में उसकी सुबह और शाम की हाजिरी नियमित रूप से लगती रही। खुली जेल में बंद कैदियों को निर्धारित नियमों और शर्तों के तहत रहने की अनुमति दी जाती है। उन्हें निश्चित समय पर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होती है और उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखी जाती है। ऐसे में किसी कैदी का पांच दिनों तक देश से बाहर रहना और जेल के रिकॉर्ड में उसकी उपस्थिति दर्ज होते रहना सामान्य चूक का मामला नहीं माना जा सकता। यदि आरोपों की पुष्टि होती है तो यह जेल प्रशासन की निगरानी व्यवस्था में गंभीर खामी का संकेत होगा।

इस पूरे मामले का खुलासा जवाहर नगर थाना पुलिस की एक कार्रवाई के दौरान हुआ। एएसपी दीपक शर्मा के अनुसार, पुलिस टीम इलाके में गश्त कर रही थी। इसी दौरान जवाहर नगर थाना क्षेत्र में एक लावारिस गाड़ी दिखाई दी, जिसकी जांच करने का निर्णय लिया गया। पुलिस ने जब वाहन की तलाशी ली तो उसमें से करीब 40 ग्राम अफीम और एक पासपोर्ट बरामद हुआ। पासपोर्ट की जांच करने पर वह श्रीगंगानगर निवासी दीक्षांत कामरा के नाम पर मिला। इसके बाद पुलिस ने वाहन और बरामद सामान के संबंध में जानकारी जुटानी शुरू की। जांच में पता चला कि जिस गाड़ी की तलाशी ली गई थी, वह दीक्षांत कामरा के भाई की थी। पासपोर्ट मिलने के बाद पुलिस के लिए यह पता लगाना जरूरी हो गया कि संबंधित व्यक्ति कौन है और उसका इस वाहन तथा बरामद अफीम से क्या संबंध है।

पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। प्रकरण का अनुसंधान सब इंस्पेक्टर नरेश कुमार को सौंपा गया। जांच के दौरान सामने आए तथ्यों और अपराध प्रमाणित पाए जाने के बाद पुलिस ने दीक्षांत कामरा को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उसे जेल भेज दिया गया। एएसपी दीपक शर्मा ने बताया कि दीक्षांत पहले से ही जयपुर के चर्चित झोटवाड़ा हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा था और नरसिंहपुर खुली जेल में बंद था। इसी दौरान उसके खिलाफ अफीम से जुड़े नए मामले में भी संलिप्तता सामने आई। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद उसके पासपोर्ट और विदेश यात्रा से संबंधित जानकारी ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया।

दीक्षांत कामरा का नाम वर्ष 2018 में जयपुर में हुए चर्चित दुष्यंत हत्याकांड से जुड़ा था। इस मामले ने उस समय काफी सुर्खियां बटोरी थीं। जानकारी के अनुसार, दीक्षांत ने अपनी प्रेमिका प्रिया सेठ के साथ मिलकर झोटवाड़ा निवासी दुष्यंत का अपहरण किया था। आरोपियों ने दुष्यंत को छोड़ने के बदले उसके पिता से 10 लाख रुपये की फिरौती मांगी थी। परिवार से फिरौती की रकम मिलने के बावजूद दुष्यंत की हत्या कर दी गई थी। इस वारदात ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी थी। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए दोनों आरोपियों की भूमिका का खुलासा किया था। बाद में अदालत ने दीक्षांत कामरा को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। सजा के बाद उसे नरसिंहपुर खुली जेल में रखा गया था।

अब उसी हत्याकांड के दोषी की कथित विदेश यात्रा ने जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब दीक्षांत कामरा आजीवन कारावास की सजा काट रहा था, तब उसके पास पासपोर्ट कैसे मौजूद रहा? उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उसका पासपोर्ट वर्ष 2016 में जारी किया गया था। वर्ष 2023 में आजीवन कारावास की सजा होने के बाद भी पासपोर्ट जब्त किए जाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्या सजा सुनाए जाने के बाद पासपोर्ट को लेकर कोई कार्रवाई की गई थी? यदि पासपोर्ट उसके पास ही था तो क्या जेल प्रशासन को इसकी जानकारी थी? क्या उसने विदेश यात्रा के लिए किसी तरह की अनुमति मांगी थी या फिर बिना अनुमति के ही देश से बाहर चला गया? इन सवालों के जवाब मिलना जरूरी है।

खुली जेल की व्यवस्था का उद्देश्य सजायाफ्ता कैदियों को निर्धारित नियमों के तहत सीमित स्वतंत्रता देते हुए उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने और पुनर्वास का अवसर उपलब्ध कराना है। इस व्यवस्था में कैदियों को सामान्य जेल की तुलना में कुछ अधिक छूट मिलती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वे निगरानी से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं। निर्धारित समय पर हाजिरी देना और नियमों का पालन करना उनकी जिम्मेदारी होती है। वहीं, जेल प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि वह कैदियों की उपस्थिति और गतिविधियों पर नियमित नजर रखे। ऐसे में यदि कोई कैदी पांच दिनों तक विदेश में रहता है और उसकी अनुपस्थिति का पता नहीं चलता, तो हाजिरी व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

इस मामले में सबसे गंभीर पहलू सुबह और शाम की नियमित हाजिरी का है। बताया जा रहा है कि 9 से 13 अक्टूबर 2025 के बीच दीक्षांत कामरा की उपस्थिति जेल के रिकॉर्ड में दर्ज होती रही। यदि वह इस दौरान थाईलैंड में था तो जेल में उसकी हाजिरी किसने लगाई? क्या किसी कर्मचारी ने बिना वास्तविक मौजूदगी की पुष्टि किए रिकॉर्ड में उसकी उपस्थिति दर्ज कर दी? क्या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से हाजिरी लगवाई गई या फिर रिकॉर्ड में जानबूझकर हेरफेर किया गया? यह भी जांच का विषय है कि उस अवधि में जेल में तैनात कर्मचारियों की ड्यूटी किसकी थी और हाजिरी दर्ज करने की जिम्मेदारी किस अधिकारी या कर्मचारी के पास थी।

जांच में पासपोर्ट की विदेश यात्रा संबंधी एंट्री और जेल के हाजिरी रजिस्टर का मिलान बेहद महत्वपूर्ण होगा। इसके साथ ही विदेश यात्रा की तारीखों, आवागमन के दस्तावेजों और संबंधित रिकॉर्ड की जांच से यह स्पष्ट हो सकता है कि दीक्षांत वास्तव में कब देश से बाहर गया और कब वापस लौटा। जेल प्रशासन के पास उपलब्ध उपस्थिति रजिस्टर, ड्यूटी रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों की पड़ताल से यह पता लगाया जा सकता है कि कथित विदेश यात्रा के दौरान उसकी हाजिरी किस प्रक्रिया के तहत दर्ज की गई थी। यदि किसी कर्मचारी की भूमिका संदिग्ध पाई जाती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई का रास्ता खुल सकता है। मामले ने यह सवाल भी खड़ा किया है कि क्या खुली जेलों में कैदियों की निगरानी केवल रजिस्टर में हाजिरी दर्ज करने तक सीमित रह गई है? कैदी की वास्तविक मौजूदगी की पुष्टि करने के लिए क्या पर्याप्त व्यवस्था है? यदि किसी बंदी को निर्धारित समय पर उपस्थित होना जरूरी है तो उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में तत्काल जांच क्यों नहीं हुई? पांच दिनों तक लगातार हाजिरी दर्ज होने के बावजूद विदेश यात्रा की जानकारी सामने नहीं आना निगरानी तंत्र की कार्यप्रणाली की समीक्षा की जरूरत बताता है। फिलहाल दीक्षांत कामरा को अफीम से जुड़े नए मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। दूसरी ओर, उसकी कथित थाईलैंड यात्रा और खुली जेल में दर्ज हाजिरी को लेकर उठे सवालों का जवाब संबंधित रिकॉर्ड की जांच के बाद ही मिल सकेगा। यह भी स्पष्ट होना बाकी है कि विदेश यात्रा के लिए कोई अनुमति ली गई थी या नहीं और पासपोर्ट जब्त करने के संबंध में जेल प्रशासन ने क्या कदम उठाए थे। यदि बिना अनुमति विदेश यात्रा और फर्जी तरीके से हाजिरी दर्ज होने के आरोप सही साबित होते हैं तो मामला केवल एक कैदी की नियमों की अनदेखी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जेल प्रशासन की जवाबदेही भी तय करनी होगी।

राजस्थान का यह मामला जेलों में बंद कैदियों की निगरानी, पासपोर्ट संबंधी नियमों और खुली जेलों की व्यवस्था को लेकर व्यापक समीक्षा की जरूरत को सामने लाता है। आजीवन कारावास की सजा काट रहे व्यक्ति की कथित विदेश यात्रा और उसी दौरान जेल में उसकी नियमित मौजूदगी दर्ज होना कई स्तरों पर जांच की मांग करता है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि पुलिस और जेल प्रशासन की जांच में कौन-कौन से तथ्य सामने आते हैं तथा इस पूरे प्रकरण में लापरवाही या मिलीभगत की जिम्मेदारी किस पर तय होती है।

पेट्रोल पंपों पर महिला सशक्तिकरण की एक नई झलक: देश भर में 10,000 से अधिक महिलाएँ जिम्मेदारियाँ संभाल रही हैं



(निडर, निष्पक्ष और तटस्थ छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत

आज हम पेट्रोल पंपों पर काम करने वाली महिलाओं के बारे में बात करेंगे। भारत में 80 महिला पेट्रोल पंप हैं। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम आदि कंपनियों को मिलाकर पूरे भारत में दस हजार से अधिक महिलाएं पेट्रोल पंपों पर काम करती हैं। अकेले भारत पेट्रोलियम में ही 6800 महिलाएं पेट्रोल पंपों पर कार्यरत हैं। इनमें से अधिकतर महिलाएं और लड़कियां मैनेजर से लेकर पंप अटेंडेंट तक के पदों पर काम करती हैं। कुछ पेट्रोल पंपों पर महिलाएं मिश्रित स्टाफ के रूप में भी काम करती नजर आती हैं।

आम तौर पर, हमारी सोच और नज़रें पेट्रोल पंपों पर केवल पुरुषों को काम करते देखने की आदी हैं। लेकिन महिलाओं ने इस क्षेत्र में पुरुष प्रधानता की बेड़ियों को तोड़ दिया है। पूरा भारतीय समाज अभी तक इस बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाया है।

इस पेट्रोल पंप पर काम करने वाली महिलाओं के लिए दो शिफ्ट हैं। पहली शिफ्ट सुबह 6:30 बजे शुरू होकर दोपहर 2:00 बजे खत्म होती है और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:15 बजे शुरू होकर रात 10:00 बजे तक चलती है। ज्यादातर पेट्रोल भरने का काम महिलाएं ही करती हैं और मैनेजर व मालिक के तौर पर भी महिलाएं ही काम करती हैं। पेट्रोल पंप पर काम करने वाली महिलाएं यूनिफॉर्म पहनकर आती हैं। उनके काम में फ्यूल डिस्पेंसर से पेट्रोल भरना, कैश संभालना, डिजिटल पेमेंट लेना, पेट्रोल पंप पर सुरक्षा उपकरणों का रखरखाव करना, पेट्रोल पंप पर ट्रैफिक होने पर मार्गदर्शन करना, यह सुनिश्चित करना कि कोई भी ग्राहक पेट्रोल पंप पर सिगरेट न पिए और माचिस आदि गिरकर आग न लगाए, शामिल हैं। इस प्रकार, अब भारत में काम के हर क्षेत्र में महिलाएं अपनी प्रतिभा दिखा रही हैं।

दवाओं की ऊंची कीमतों और 400% तक के अंतर पर सुप्रीम कोर्ट में सवाल: स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के खिलाफ चिंताएं



(निडर, निष्पक्ष और तटस्थ छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत

एक व्यक्ति स्वस्थ होने के लिए दवा लेता है। यानी, दवा का उद्देश्य व्यक्ति को ठीक करना है। लेकिन जब दवा का खर्च ही मरीज और उसके परिवार के लिए असहनीय पीड़ा का कारण बन जाता है, तो स्वास्थ्य प्रणाली की प्राथमिकताओं पर गंभीर प्रश्न उठते हैं। बीमारी किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति पर निर्भर नहीं करती। चाहे गरीब हो या मध्यम वर्ग का, जब किसी परिवार को कैंसर, हृदय रोग या अन्य गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ता है, तो पहली चिंता यही होती है कि इलाज का खर्च कैसे उठाया जा

दिवाली-छठ पर घर लौटने वालों की उमड़ी भीड़, सूरत-उधना से दो दिन में 60 हजार यात्री रवाना

रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों का भारी दबाव, होल्डिंग एरिया भी पड़े छोटे; 15 घंटे में 12 ट्रेनों से 43,800 यात्रियों ने किया सफर, स्पेशल ट्रेनों और तीन यात्री सुविधा केंद्रों से संभाली गई व्यवस्था

सूरत। दीपावली और छठ पूजा के अवसर पर अपने गृह नगर जाने वाले यात्रियों की भीड़ ने सूरत और उधना रेलवे स्टेशनों पर दबाव बढ़ा दिया है। बिहार और उत्तर प्रदेश जाने वाले यात्रियों की संख्या में अचानक हुई बढ़ोतरी के कारण दोनों स्टेशनों पर दिनभर गहमागहमी का माहौल बना रहा। हालात ऐसे हो गए कि यात्रियों से भरे होल्डिंग एरिया में पैर रखने तक की जगह नहीं बची। इसके बावजूद रेलवे प्रशासन की ओर से अतिरिक्त ट्रेनों के संचालन, यात्री सुविधा केंद्रों और कतारबद्ध व्यवस्था के जरिए भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। शनिवार और रविवार को दो दिनों में करीब 50 से 60 हजार यात्रियों को उनके गृह नगरों के लिए रवाना किया गया। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, इस बार यात्रियों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में लगभग दोगुनी रही है।

पश्चिम रेलवे के डीआरएम पंकज सिंह ने बताया कि दीपावली की छुट्टियों और कर्मचारियों को वेतन मिलने के बाद शुक्रवार से ही बड़ी संख्या में लोगों ने अपने घरों की ओर जाना शुरू कर दिया था। शुक्रवार को नियमित ट्रेनों के साथ छह से सात स्पेशल ट्रेनें चलाई गईं, जिनके माध्यम से करीब 30 से 35 हजार यात्रियों को रवाना किया गया। इसके बाद शनिवार और रविवार को भी यात्रियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती रही। आम दिनों में शनिवार और रविवार को करीब 15 हजार यात्री सफर करते हैं। पिछले वर्ष त्योहारों के दौरान यह संख्या बढ़कर लगभग 35 हजार तक पहुंची थी, लेकिन इस बार यात्रियों की आवाजाही ने पुराने आंकड़ों को पीछे छोड़ दिया।



यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे ने उधना स्टेशन पर लगातार विशेष ट्रेनों का संचालन किया। उद्देश्य यह था कि यात्रियों को घंटों तक स्टेशन पर इंतजार न करना पड़े और भीड़ एक साथ प्लेटफॉर्म पर न पहुंचे। इसके लिए दिन और रात के अलग-अलग समय पर ट्रेनों की व्यवस्था की गई। शनिवार सुबह 5:30 बजे, 8:30 बजे, 10:10 बजे और 11:30 बजे ट्रेनें रवाना की गईं। दोपहर एक बजे भी विशेष ट्रेन चलाई गई। शाम और रात के समय जब यात्रियों की संख्या और बढ़ी, तब रात 10 बजे, 11:30 बजे और देर रात 1:30 बजे तक ट्रेनों का संचालन जारी रखा गया। इसके बाद रविवार तड़के तीन बजे, पांच बजे, सात बजे और आठ बजे भी यात्रियों को उनके गंतव्य की ओर भेजने के लिए ट्रेनें चलाई गईं।

ताप्ती गंगा, जयनगर स्पेशल और अंत्योदय एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों के माध्यम से उत्तर प्रदेश और बिहार की ओर जाने वाले यात्रियों को रवाना किया गया। रेलवे ने यात्रियों की संख्या और उपलब्ध ट्रेनों के बीच तालमेल बनाते हुए जरूरत के अनुसार अतिरिक्त सेवाएं संचालित कीं। लगातार ट्रेनों के संचालन से स्टेशन पर जमा हो रही भीड़ को अलग-अलग समय पर रवाना करने में मदद मिली। हालांकि, यात्रियों का दबाव इतना अधिक था कि कई बार होल्डिंग एरिया में भी जगह की कमी महसूस हुई।

रेलवे प्रशासन के अनुसार, सात और आठ नवंबर के बीच महज 15 घंटे में नौ स्पेशल और तीन नियमित ट्रेनों सहित कुल 12 ट्रेनें चलाई गईं। इन ट्रेनों के जरिए करीब 43,500 से 43,800 यात्रियों की आवाजाही व्यवस्थित की गई। जयनगर, मधुबनी, कानपुर और ब्रह्मपुर जैसे उत्तर और पूर्वी भारत के प्रमुख गंतव्यों के लिए यात्रियों की भारी मांग रही। इन रूटों पर जाने वाले लोगों की संख्या अधिक होने के कारण प्लेटफॉर्म और होल्डिंग एरिया में विशेष निगरानी रखी गई। प्लेटफॉर्म नंबर छह सहित अन्य प्लेटफॉर्म पर रेलकर्मियों के बीच समन्वय बनाकर ट्रेनों का संचालन किया गया, ताकि यात्रियों को सुरक्षित तरीके से कोच तक पहुंचाया जा सके।

भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे ने उधना स्टेशन परिसर में करीब 14 से 15 हजार वर्गमीटर क्षेत्र में तीन यात्री सुविधा केंद्र विकसित किए। इन केंद्रों को बफर जोन के रूप में इस्तेमाल किया गया, ताकि सभी यात्री एक साथ प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर अव्यवस्था पैदा न करें। पहला यात्री सुविधा केंद्र लगभग 6,500 वर्गमीटर, दूसरा करीब 2,500 वर्गमीटर और तीसरा लगभग 3,500 वर्गमीटर क्षेत्र में बनाया गया है। इन केंद्रों में यात्रियों के बैठने, पीने के पानी, बिजली, पंखे और शौचालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अलावा अतिरिक्त टिकट खिड़कियां और सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, जिससे टिकट व्यवस्था के साथ सुरक्षा और निगरानी को बेहतर बनाया जा सके।

इन सुविधा केंद्रों पर यात्रियों को पहले बैठाया जाता है। संबंधित ट्रेन के आने का समय होने पर उन्हें निर्धारित कतारों में खड़ा कर प्लेटफॉर्म की ओर भेजा जाता है। इसके बाद रेलकर्मियों की निगरानी में यात्रियों को उनके कोच तक पहुंचाया जाता है। इस व्यवस्था का उद्देश्य प्लेटफॉर्म पर एक साथ भीड़ जमा होने, धक्का-मुक्की और भगदड़ जैसी स्थिति की आशंका को कम करना है। विशेष रूप से परिवारों, बच्चों और बुजुर्ग यात्रियों को ट्रेन तक पहुंचाने में इस व्यवस्था से सहायता मिली।

रेलवे की ओर से की गई व्यवस्थाओं को यात्रियों ने भी उपयोगी बताया। बिहार जाने वाले यात्री मुन्ना कुमार सिंह ने बताया कि उन्हें ट्रेन में चढ़ने के लिए कतार में खड़ा होना पड़ा, लेकिन धक्का-मुक्की का सामना नहीं करना पड़ा और उन्हें आसानी से जगह मिल गई। उन्होंने जयनगर स्पेशल ट्रेन चलाने के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि त्योहार के समय ऐसी अतिरिक्त ट्रेनों से घर जाने वाले लोगों को राहत मिलती है। उनके मुताबिक, यात्रियों की संख्या बहुत अधिक होने के बावजूद व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास किया गया।

वहीं, परिवार के साथ अंत्योदय एक्सप्रेस से यात्रा कर रहीं नीलम देवी ने बताया कि ट्रेन का इंतजार करते समय यात्री सुविधा केंद्र में पंखे और पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था थी। उन्होंने कहा कि प्रतीक्षा के दौरान परिवार के साथ बैठने की जगह मिलना राहत की बात रही। रेलवे कर्मचारियों की मौजूदगी और कतारबद्ध तरीके से यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर भेजने के कारण अनावश्यक धक्का-मुक्की नहीं हुई और ट्रेन में बैठना भी अपेक्षाकृत आसान रहा।

त्योहारी सीजन में सूरत और उधना से उत्तर प्रदेश तथा बिहार जाने वाले यात्रियों की संख्या हर वर्ष बढ़ती है। सूरत में बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों के लोग रोजगार और कारोबार के सिलसिले में रहते हैं। दीपावली और छठ पूजा के अवसर पर वे अपने परिवारों के साथ त्योहार मनाने के लिए गृह नगर लौटते हैं। इस वजह से त्योहार से पहले रेलवे स्टेशनों पर अचानक यात्रियों का दबाव बढ़ जाता है। इस बार दो दिनों में 50 से 60 हजार यात्रियों के रवाना होने का आंकड़ा इस भीड़ की व्यापकता को दर्शाता है। रेलवे प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यात्रियों को सुरक्षित तरीके से स्टेशन परिसर से प्लेटफॉर्म और फिर ट्रेन तक पहुंचाने की रही। अतिरिक्त ट्रेनों के संचालन के साथ यात्री सुविधा केंद्रों को बफर जोन के रूप में इस्तेमाल करने से भीड़ को अलग-अलग हिस्सों में बांटने में मदद मिली। अब त्योहारों के दौरान आगे भी यात्रियों की आवाजाही पर नजर रखी जा रही है, ताकि घर लौटने वाले लोगों को सुरक्षित और व्यवस्थित यात्रा की सुविधा मिल सके।

वन मंत्री गणेश नाइक ने आदिवासी किसानों के बीच मनाई दिवाली, खेतों में पहुंचकर देखा फसल नुकसान

मुंबई। सूखे और फसल नुकसान की मार झेल रहे किसानों के साथ दिवाली की खुशियां साझा करने की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अपील पर राज्य के वन मंत्री गणेश नाइक ने ठाणे जिले के शहापुर तहसील स्थित करपटवाड़ी (धधारे) गांव पहुंचकर आदिवासी परिवारों और किसानों के बीच त्योहार मनाया। लक्ष्मी पूजा के अवसर पर आयोजित इस दौरे में उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं और खेतों में पहुंचकर प्राकृतिक आपदा से प्रभावित फसलों की स्थिति का जायजा लिया। मंत्री ने किसानों को भरोसा दिलाया कि मुश्किल समय में सरकार उनके साथ खड़ी है और उनकी समस्याओं को गंभीरता से लिया जाएगा।

गांव पहुंचने के बाद गणेश नाइक ने किसानों के साथ खेतों का दौरा किया। उन्होंने धान, उड़द, नागली और खुरासानी की फसलों का निरीक्षण किया तथा किसानों से खेती की मौजूदा स्थिति के बारे में विस्तार से जानकारी ली। किसानों ने उन्हें फसल नुकसान, मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों और खेती के दौरान सामने आ रही परेशानियों से अवगत कराया। मंत्री ने खेतों में जाकर नुकसान का प्रत्यक्ष जायजा लिया, ताकि किसानों की वास्तविक स्थिति और उनकी जरूरतों को समझा जा सके। इस दौरे का उद्देश्य केवल औपचारिक मुलाकात करना नहीं, बल्कि संकट से गुजर रहे किसानों के बीच पहुंचकर उनकी परेशानियों को सुनना और उन्हें सहयोग का भरोसा देना रहा।

दिवाली जैसे प्रमुख त्योहार पर आदिवासी परिवारों के साथ समय बिताकर मंत्री ने यह संदेश देने का प्रयास किया कि किसानों की तकलीफ के समय जनप्रतिनिधियों और सरकार को उनके बीच मौजूद रहना चाहिए। फसल नुकसान के कारण कई परिवारों के सामने आर्थिक चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। ऐसे में त्योहार के अवसर पर ग्रामीणों से मुलाकात और उनकी समस्याएं सुनना उनके लिए महत्वपूर्ण रहा। मंत्री ने किसानों की बातों को सुना और उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं को संबंधित स्तर पर उठाया जाएगा।

इस अवसर पर धधारे ग्राम पंचायत की ओर से वन मंत्री का स्वागत और सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान आदिवासी परिवारों को खाद्य सामग्री के किट और दिवाली उपहार वितरित किए गए। त्योहार के मौके पर मिली इस सहायता से ग्रामीण परिवारों में खुशी देखने को मिली। आयोजन के माध्यम से जरूरतमंद परिवारों के साथ दिवाली की खुशियां साझा करने के साथ उनके जीवन की कठिनाइयों को समझने का प्रयास भी किया गया।

कार्यक्रम में मौजूद पूर्व विधायक पांडुरंग बरोरा ने किसानों को भरोसा दिलाया कि फसल नुकसान के लिए उन्हें शत-प्रतिशत मुआवजा दिलाने के उद्देश्य से हरसंभव प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों की मांगों और समस्याओं को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तक पहुंचाया जाएगा, ताकि प्रभावित परिवारों को उचित न्याय मिल सके। उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया कि उनकी आवाज सरकार तक पहुंचाने और उन्हें राहत दिलाने के लिए लगातार प्रयास किए जाएंगे। इस दौरे में पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल, पूर्व विधायक पांडुरंग बरोरा, शहापुर के उप वन संरक्षक दीपेश मल्होत्रा, खंड विकास अधिकारी बी.एच. राठौड़ और तहसील कृषि अधिकारी कुमार जाधव सहित वन, राजस्व और कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। स्थानीय पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। अधिकारियों की मौजूदगी में किसानों की समस्याओं और फसल नुकसान से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई।

दिवाली के अवसर पर वन मंत्री का आदिवासी किसानों के बीच पहुंचना ग्रामीणों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल रही। खेतों में जाकर फसलों की स्थिति देखना, किसानों की परेशानियां सुनना और प्रभावित परिवारों को खाद्य सामग्री व त्योहार के उपहार देना इस दौरे के प्रमुख पहलू रहे। अब किसानों को उम्मीद है कि उनकी समस्याओं और मुआवजे की मांग पर सरकार की ओर से जल्द सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे।

त्योहारों की भीड़ के बीच पश्चिम रेलवे चलाएगी दो विशेष ट्रेनें

मुंबई। त्योहारों के दौरान यात्रियों की बढ़ती संख्या और ट्रेनों में अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए पश्चिम रेलवे ने विशेष किराये पर दो स्पेशल ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया है। यात्रियों को राहत देने के उद्देश्य से बांद्रा टर्मिनस-खातीपुरा और उधना-बरौनी के बीच विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। इन ट्रेनों के संचालन से राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की ओर जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त रेल सुविधा मिलेगी। पश्चिम रेलवे के जनसंपर्क विभाग के अनुसार, दोनों स्पेशल ट्रेनों में यात्रियों की सुविधा के लिए एसी द्वितीय श्रेणी, एसी तृतीय श्रेणी, स्लीपर और सामान्य द्वितीय श्रेणी के कोच लगाए जाएंगे।



बांद्रा टर्मिनस और खातीपुरा के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन दोनों दिशाओं में संचालित होगी। ट्रेन संख्या 09718 बांद्रा टर्मिनस-खातीपुरा स्पेशल 12 नवंबर 2026 को शाम 4:30 बजे बांद्रा टर्मिनस से रवाना होगी और अगले दिन दोपहर 3:05 बजे खातीपुरा पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 09717 खातीपुरा-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल 11 नवंबर को दोपहर 3:15 बजे खातीपुरा से प्रस्थान करेगी और अगले दिन दोपहर 3:15 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी।

इस ट्रेन का दोनों दिशाओं में कई महत्वपूर्ण स्टेशनों पर ठहराव निर्धारित किया गया है। इनमें बोरीवली, वापी, वलसाड, सूरत, भरूच, वडोदरा, गोधरा, रतलाम, मंदसौर, नीमच, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बिजयनगर, नसीराबाद, अजमेर, किशनगढ़ और जयपुर शामिल हैं। इन स्टेशनों पर ठहराव से गुजरात और राजस्थान के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को विशेष सुविधा मिलेगी। खासकर सूरत और आसपास के क्षेत्रों से राजस्थान जाने वाले यात्रियों को इस ट्रेन का लाभ मिल सकेगा।

दूसरी स्पेशल ट्रेन उधना और बरौनी के बीच चलाई जाएगी। ट्रेन संख्या 09039 उधना-बरौनी स्पेशल 10 नवंबर को दोपहर 3 बजे उधना से रवाना होगी और 12 नवंबर को सुबह 4 बजे जयनगर पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 09040 बरौनी-उधना स्पेशल 12 नवंबर को सुबह 8:30 बजे बरौनी से रवाना होकर 14 नवंबर को रात 1:30 बजे उधना पहुंचेगी। इस ट्रेन के संचालन से गुजरात से बिहार की ओर जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध होगा।

उधना-बरौनी स्पेशल ट्रेन दोनों दिशाओं में कई प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी। इसके ठहराव में चलथान, बारडोली, नंदुरबार, दोंडाईचा, अमलनेर, धरणगांव, भुसावल, खंडवा, इटारसी, जबलपुर, कटनी, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर, आरा, दानापुर, पाटलिपुत्र, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर स्टेशन शामिल हैं। इन ठहरावों के माध्यम से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के विभिन्न क्षेत्रों के यात्रियों को यात्रा की सुविधा मिलेगी।

पश्चिम रेलवे की ओर से विशेष किराये पर इन ट्रेनों का संचालन त्योहारों के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त मांग को पूरा करने की दिशा में किया जा रहा है। नियमित ट्रेनों में भीड़ बढ़ने के कारण कई मार्गों पर आरक्षित सीटों की उपलब्धता सीमित हो जाती है। ऐसे में स्पेशल ट्रेनों से यात्रियों को वैकल्पिक सेवा मिलेगी और लंबी दूरी की यात्रा की योजना बनाने में सहूलियत होगी।

एक जरूरी विवरण: दी गई सूचना में ट्रेन संख्या 09039 के उधना से रवाना होकर जयनगर पहुंचने और वापसी ट्रेन 09040 के बरौनी से चलने का उल्लेख है। शीर्षक में भी उधना-बरौनी लिखा है। प्रकाशन से पहले गंतव्य और वापसी के स्टेशन का विवरण पश्चिम रेलवे की आधिकारिक सूचना से एक बार मिलान कर लेना उचित होगा।

काली चौदस की रात सूरत में आग की 25 घटनाएं, पूरी रात दौड़ती रहीं दमकल की गाड़ियां

सूरत। दिवाली के उत्साह और आतिशबाजी के बीच काली चौदस की रात सूरत शहर में आग लगने की घटनाओं ने दमकल विभाग को पूरी रात व्यस्त रखा। शहर के अलग-अलग इलाकों में पटाखों की चिंगारियों और शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की कुल 25 घटनाएं सामने आईं। ऊंची इमारतों, घरों, दुकानों, खेतों, झोपड़ियों, खुले प्लॉट और वाहनों तक आग पहुंचने से कई स्थानों पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। रात करीब 10 बजे से सुबह तक फायर ब्रिगेड की टीमें लगातार घटनास्थलों पर पहुंचती रहीं और आग बुझाने के साथ बचाव कार्य में जुटी रहीं। दमकलकर्मियों की तत्परता से सभी जगहों पर आग पर काबू पा लिया गया और कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई।

फायर कंट्रोल रूम के अनुसार, काली चौदस की रात आग लगने, शॉर्ट सर्किट और रेस्क्यू से संबंधित कुल 25 इमरजेंसी कॉल दर्ज की गईं। इनमें सबसे अधिक घटनाएं खुले प्लॉट, झाड़ियों और कचरे के ढेर में आग लगने की थीं। कुल कॉल में से 12 मामले खुले प्लॉट, झाड़ियों और कचरे में आग लगने के थे। इसके अलावा ऊंची इमारतों, घरों और दुकानों में आग लगने की पांच घटनाएं दर्ज की गईं। खुले मैदानों और झोपड़ियों में आग की चार तथा वाहनों में आग लगने की दो कॉल मिलीं। इसके अलावा गैस लीकेज, बिजली की डीपी में स्पार्किंग, बाथरूम में फंसे व्यक्ति को बाहर निकालने और सांप पकड़ने जैसी आपात स्थितियों में भी दमकल विभाग की टीमों को मौके पर पहुंचना पड़ा।



शहर के पॉश इलाकों में स्थित ऊंची इमारतें भी आग की घटनाओं से अछूती नहीं रहीं। वेसू की वीआईपी रोड स्थित माइलस्टोन एलीट्स बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर आग लगने की सूचना मिली। इसी तरह सिटीलाइट में कोटक महिंद्रा बैंक वाली गली की गोल्डन एवेन्यू बिल्डिंग की आठवीं मंजिल पर आग लग गई। इन घटनाओं के कारण संबंधित परिसरों में लोगों के बीच चिंता का माहौल बन गया। दमकल की टीमें तत्काल मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया। इसके अलावा डिंडोली और पर्वत पाटिया क्षेत्र में नीलगिरी के पास दीपाली पार्क स्थित शुभम हाइट्स के सामने राज रेजिडेंसी बिल्डिंग में भी आग लगने की घटना सामने आई। दमकलकर्मियों ने समय रहते आग पर नियंत्रण कर लिया।

पटाखों से निकली चिंगारियों ने शहर के बाहरी इलाकों में खेतों और झोपड़ियों को भी अपनी चपेट में लिया। दांडी रोड पर आनंद एम्पायर के पास गन्ने के खेत में आग लगने की घटना हुई। जहांगीरपुरा में वैष्णोदेवी स्काई के पास तथा कामरेज-अंबाजी रोड स्थित एक खेत में भी आग की सूचना मिलने पर दमकल की टीमें पहुंचीं। पिपलोद में राहुलराज मॉल के पास पेड़ों और झोपड़ियों में आग लगने से आसपास के क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। वहीं पर्वत पाटिया चौराहे और मोटा वराछा में खड़े वाहनों में भी आग लगने की घटनाएं दर्ज की गईं। दमकलकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग को फैलने से रोकने के लिए कार्रवाई की।

काली चौदस की रात आग के अलावा गैस और बिजली से जुड़ी आपात स्थितियां भी सामने आईं। सुमन डेयरी रोड पर शांतिनिकेतन के पास गैस पाइपलाइन में लीकेज की सूचना मिलने पर दमकल विभाग की टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई की। सुबह पालनपुर फायर स्टेशन के सामने बिजली की डीपी में शॉर्ट सर्किट होने की घटना सामने आई। इसी तरह योगी चौक के पास जीईबी के तारों में स्पार्किंग होने की सूचना मिली। इन घटनाओं में किसी बड़े हादसे की आशंका को देखते हुए दमकलकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली।

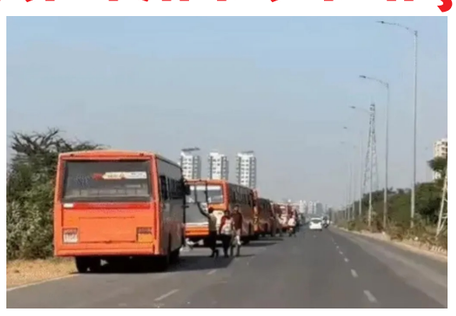
गौरवपथ रोड पर शिव रिक्शा के पास स्थित एक बंद मेडिकल स्टोर से धुआं निकलने की सूचना भी फायर कंट्रोल रूम को मिली। दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की और आग बुझाने की कार्रवाई की। इसके अलावा अडाजन के हनी पार्क रोड, गोकुलम डेयरी के पास, पालनपुर कैनाल रोड, अलथान, सरथाणा और वेसू की वीआईपी रोड सहित कई इलाकों में रोड डिवाइडर, खुले प्लॉट और कचरे के ढेर में आग लगने की कॉल मिलीं। इन स्थानों पर पटाखों की चिंगारियों से आग सुलगने की आशंका जताई गई।

त्योहार के दौरान लगातार मिल रही कॉल के कारण दमकल विभाग की टीमें पूरी रात एक स्थान से दूसरे स्थान तक दौड़ती रहीं। कहीं खुले प्लॉट में लगी आग बुझानी पड़ी तो कहीं ऊंची इमारतों और खेतों में पहुंची आग पर नियंत्रण करना पड़ा। इसके साथ ही बिजली की स्पार्किंग और गैस लीकेज जैसी घटनाओं में भी सतर्कता बरतनी पड़ी। हालांकि आग की 25 घटनाओं के बावजूद दमकलकर्मियों की त्वरित कार्रवाई से किसी बड़ी जनहानि की सूचना नहीं मिली। काली चौदस की रात की इन घटनाओं ने एक बार फिर त्योहारों के दौरान आतिशबाजी करते समय सावधानी बरतने और ज्वलनशील कचरे तथा खुले स्थानों के आसपास विशेष सतर्कता रखने की जरूरत को सामने ला दिया।

दिवाली पर सूरत एसटी डिवीजन ने 1300 अतिरिक्त बसें चलाकर कमाए 2.59 करोड़ रुपये

सूरत। दिवाली और नववर्ष के त्योहारों पर अपने घर-परिवार के बीच पहुंचने की चाह में सूरत से बड़ी संख्या में लोगों ने अपने गृह नगरों का रुख किया। यात्रियों की बढ़ती भीड़ और परिवहन की अतिरिक्त मांग को देखते हुए गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (जीएसआरटीसी) के सूरत डिवीजन ने विशेष व्यवस्था करते हुए करीब 1300 अतिरिक्त बसों का संचालन किया। चार दिनों तक चले इस विशेष परिवहन अभियान के दौरान एसटी विभाग ने 2 करोड़ 59 लाख 96 हजार 164 रुपये की आय अर्जित की। इस दौरान कुल 61,518 यात्रियों ने बसों से सफर कर अपने गंतव्य तक पहुंचने की सुविधा प्राप्त की।

एसटी डिवीजन के आंकड़ों के अनुसार, 4 से 7 नवंबर के बीच संचालित इन अतिरिक्त बसों ने कुल 4 लाख 63 हजार 636 किलोमीटर की दूरी तय की। इस दौरान प्रति किलोमीटर औसत आय 56.07 रुपये रही। त्योहारों के अवसर पर सूरत में रहने वाले प्रवासी परिवारों के लिए एसटी बसें अपने गृह नगर पहुंचने का प्रमुख साधन बनीं। खासकर सौराष्ट्र, पंचमहल, दाहोद और उत्तर-मध्य गुजरात की ओर जाने वाले यात्रियों की संख्या अधिक रही। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग मार्गों पर अतिरिक्त फेरों की व्यवस्था की गई, ताकि लोगों को बसों के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े।



दिवाली से ठीक पहले 6 नवंबर को यात्रियों की सबसे अधिक आवाजाही देखने को मिली। इस दिन सूरत एसटी डिवीजन ने 500 से अधिक ट्रिप संचालित कीं, जिनमें 26,638 यात्रियों ने सफर किया। एक ही दिन में बसों ने 2 लाख 1 हजार 754 किलोमीटर की दूरी तय की और विभाग को 1 करोड़ 10 लाख 22 हजार 955 रुपये की आय प्राप्त हुई। चार दिनों के विशेष संचालन में यह एक दिन की सबसे अधिक आय रही। इससे स्पष्ट हुआ कि त्योहार से पहले घर लौटने वाले यात्रियों की संख्या में अचानक बड़ा इजाफा हुआ था।

इसके अगले दिन यानी 7 नवंबर को भी यात्रियों की आवाजाही जारी रही। इस दिन 260 ट्रिप के माध्यम से 11,954 यात्रियों ने यात्रा की। इन फेरों से एसटी विभाग को करीब 59.74 लाख रुपये की आय हुई। यात्रियों की संख्या और बसों के संचालन को देखते हुए विभाग के लिए यह अवधि व्यस्त रही। त्योहारों के दौरान नियमित बस सेवाओं के साथ अतिरिक्त बसों का संचालन करने से यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के अधिक विकल्प मिले।

सूरत से पंचमहल और दाहोद क्षेत्र की ओर जाने वाली बसों में विशेष रूप से भीड़ रही। झालोद, दाहोद और रामनगर-झालोद मार्ग पर यात्रियों की मांग अधिक देखी गई। इसके अलावा सौराष्ट्र क्षेत्र के अमरेली, महुवा, सावरकुंडला और गरियाधार जाने वाली बसों में भी बड़ी संख्या में यात्रियों ने सफर किया। इन मार्गों पर यात्रियों की संख्या को देखते हुए अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की गई। त्योहारों के दौरान सूरत में कामकाज और रोजगार के सिलसिले में रहने वाले लोगों के लिए अपने परिवारों के साथ दिवाली मनाने का अवसर महत्वपूर्ण होता है। इसी वजह से इन दिनों लंबी दूरी के मार्गों पर यातायात का दबाव बढ़ जाता है।

इस बार सोसायटियों और विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से की गई सामूहिक बस बुकिंग को भी अच्छा प्रतिसाद मिला। समूह में यात्रा करने वाले लोगों ने पहले से बसों की बुकिंग कराई, जिससे उनके लिए एक साथ गृह नगर पहुंचना आसान हुआ। अकेले 6 नवंबर को ग्रुप बुकिंग के तहत 164 बसों का संचालन किया गया। इन बसों के माध्यम से विभाग को 37.62 लाख रुपये की आय हुई। सामूहिक बुकिंग के कारण यात्रियों को अलग-अलग बसों में सीट तलाशने की परेशानी से भी राहत मिली और एसटी विभाग को अतिरिक्त यात्रियों को व्यवस्थित तरीके से परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने में मदद मिली।

त्योहारों के दौरान सूरत जैसे औद्योगिक शहर से बड़ी संख्या में श्रमिकों, कर्मचारियों और व्यापार से जुड़े लोगों का अपने गांवों की ओर जाना सामान्य बात है। ऐसे समय में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। एसटी डिवीजन की ओर से 1300 अतिरिक्त बसों का संचालन इसी बढ़ती मांग को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम रहा। चार दिनों में 61,518 यात्रियों को सफर की सुविधा देने के साथ विभाग ने करीब 2.60 करोड़ रुपये की आय भी अर्जित की। आंकड़े बताते हैं कि दिवाली और नववर्ष के अवसर पर सूरत से गृह नगरों की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए अतिरिक्त बस सेवाएं काफी उपयोगी साबित हुईं।

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के मिसिंग लिंक पर मरम्मत, दो लेन बंद

मुंबई। मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले वाहन चालकों को फिलहाल खोपोली के पास कुछ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मिसिंग लिंक को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली करीब 100 मीटर लंबी सड़क की हालत खराब होने के कारण महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास महामंडल (एमएसआरडीसी) ने इसकी मरम्मत शुरू कर दी है। पांच लेन वाले इस हिस्से में फिलहाल दो लेन को वाहनों के आवागमन के लिए बंद रखा गया है। मरम्मत के लिए एपॉक्सी डामर का इस्तेमाल किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार, यह काम अगले चार से पांच दिनों में पूरा होने की संभावना है।

मुंबई और पुणे के बीच यात्रा को तेज, सुगम और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से एमएसआरडीसी ने 13.3 किलोमीटर लंबे मिसिंग लिंक का निर्माण किया है। इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय करीब 30 मिनट तक कम करना है। मिसिंग लिंक शुरू होने के बाद मुंबई-पुणे मार्ग पर सफर करने वाले यात्रियों को काफी सहूलियत मिली है। हालांकि, इस नए मार्ग को खोपोली के पास मुख्य एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाली करीब 100 मीटर लंबी सड़क की स्थिति खराब हो गई है। सड़क पर आई इस समस्या को लेकर वाहन चालकों की ओर से कई शिकायतें मिलने के बाद एमएसआरडीसी ने मरम्मत का निर्णय लिया।

अधिकारियों के मुताबिक, बारिश के मौसम में इस हिस्से की मरम्मत करना संभव नहीं था। मौसम अनुकूल होने के बाद अब काम शुरू किया गया है। सड़क की खराब स्थिति को सुधारने के लिए एपॉक्सी डामर तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। इसके तहत सड़क की क्षतिग्रस्त सतह को ठीक कर उसे दोबारा मजबूत और उपयोग के योग्य बनाया जा रहा है। मरम्मत कार्य के दौरान यातायात को पूरी तरह रोकने के बजाय सीमित लेनों के माध्यम से वाहनों की आवाजाही जारी रखी गई है।



एमएसआरडीसी के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, करीब 100 मीटर लंबे हिस्से की दो लेनों में मरम्मत का काम 3 नवंबर से शुरू किया गया है। इसके चलते मिसिंग लिंक की ओर जाने वाले वाहनों के लिए फिलहाल तीन लेन उपलब्ध हैं। पांच लेन में से दो लेन बंद रहने के कारण यातायात का दबाव शेष लेनों पर बढ़ सकता है। खासकर दीपावली के दौरान बड़ी संख्या में लोग मुंबई और आसपास के इलाकों से अपने गांवों की ओर जा रहे हैं। ऐसे में एक्सप्रेसवे पर वाहनों की आवाजाही अधिक रहने से यात्रियों को कुछ असुविधा हो रही है। हालांकि, एमएसआरडीसी अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल उपलब्ध तीन लेन से यातायात संचालित करने के लिए पर्याप्त जगह है।

मरम्मत कार्य को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने की योजना बनाई गई है। पहले बंद की गई दो लेनों का काम पूरा किया जाएगा। इसके बाद शेष तीन लेनों की मरम्मत शुरू होगी, ताकि पूरे पांच लेन वाले हिस्से को दुरुस्त किया जा सके। अधिकारियों के अनुसार, पूरी प्रक्रिया अगले चार से पांच दिनों में समाप्त होने की उम्मीद है। विभाग का प्रयास है कि दीपावली के दौरान बढ़े हुए यातायात के बावजूद मरम्मत कार्य निर्धारित समय में पूरा कर लिया जाए।

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र के सबसे व्यस्त मार्गों में शामिल है। इस पर रोजाना बड़ी संख्या में निजी वाहन, बसें और मालवाहक वाहन गुजरते हैं। त्योहारों के दौरान यातायात का दबाव सामान्य दिनों की तुलना में अधिक हो जाता है। ऐसे समय में सड़क के किसी हिस्से पर मरम्मत या लेन बंद होने से वाहन चालकों को परेशानी हो सकती है। एमएसआरडीसी का कहना है कि उपलब्ध तीन लेनों के जरिए आवागमन जारी रखा गया है और मरम्मत जल्द पूरी करने